प्रेरणा स्रोत
स्व. श्री यशवंतजी घोड़ावत

RNI No. MPHIN/2018/76422

बेबाकी के साथ...सच

माही की गूंज

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

सुविचार

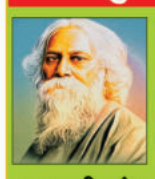

बर्तन में रखा पानी हमेशा चमकता है और समुद्र का पानी हमेशा गहरे रंग का अस्पष्ट होता है। लघु सत्य के शब्द हमेशा स्पष्ट होते हैं, महान सत्य मौन रहता है।

गुरू रवींद्रनाथ टैगोर

वर्ष-06, अंक - 41 (साप्ताहिक) | खवासा, गुरुवार 04 जुलाई 2024 | पृष्ठ-8, मूल्य -5 रुपए

नए टैक्स नहीं होने से जनता को मिली राहत,

यादव सरकार पेश किया अपना पहला बजट

भोपाल।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने अपना पहला बजट मध्य प्रदेश की विधानसभा में बुधवार को पेश किया। एमपी के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कथित नर्सिंग कॉलेज घोटाले के मुद्दे को लेकर विपक्षी कांग्रेस के हंगामे के बीच 2024-25 के लिए बजट पेश किया।

मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार ने 3.75 लाख करोड़ का बजट सदन में पेश किया है। सरकार के पहले पूर्ण बजट में आम लोगों को राहत देते हुए उनके पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स का बोझ नहीं लगाया गया है।

सरकार की ओर से महिलाओं, किसानों, युवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा सेक्टर में विशेषतौर से फोकस किया गया है। इसी के साथ ही ऊर्जा सेक्टर पर भी यादव सरकार की प्राथमिकता रहेगी। बजट पेश करने के लिए जैसे ही सदन की कार्रवाई बुधवार को शुरू हुई, विपक्ष के नेता उमंग सिंघार और अन्य कांग्रेस सदस्यों ने कथित घोटाले के सिलसिले में मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग की।

विपक्ष के सदस्यों ने सदन में खड़े होकर सारंग के इस्तीफे की मांग की। बजट भाषण शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विपक्ष को यह मुद्दा उठाने के लिए मंगलवार को पर्याप्त समय दिया गया था और उन्हें बजट पेश किए जाने के दौरान सदन की परंपरा के अनुसार इसमें भाग लेना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मामले में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि विधानसभा की कार्यवाही सदन के नियमों और परंपराओं के अनुसार चलेगी और विपक्ष को उचित प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायतें उठानी चाहिए।

विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा कि सदन के नियमों में ढील दिए जाने के बाद विपक्ष मंगलवार को यह मुद्दा उठा चुका है। विपक्षी सदस्यों ने विजयवर्गीय की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और वे आसन के सामने खड़े होकर नारेबाजी करते रहे और फिर वहीं बैठ गए।

मोहन यादव सरकार को बजट के लिए मिले 3000 सुझाव

मोहन यादव सरकार ने सदन में बजट पेश करने से पहले लोगों से सुझाव मांगे थे। समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने बजट पर अपने सुझाव साझा किए थे। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट के लिए 3000 सुझाव प्राप्त हुए थे।

महिला, किसान और युवाओं पर फोकस

मुख्यमंत्री मोहन यादव के बजट में महिलाओं को लुभाने की पूरी कोशिश की गई है। किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही खेती के लिए नई तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। इसके अलावा, बजट में यादव सरकार ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने के साथ ही स्वरोजगार से जोड़ने पर भी फोकस किया है।

बजट की खास बातें

- पिछड़ों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कार्ययोजन।
- महिलाओं, किसानों-युवाओं सहित अन्य वर्गों के लिए चलाई जा रही योजनाएं जारी रहेंगी।
- केंद्र से अतिरिक्त 3800 करोड़ की धनराशि मिलेगी, जिसे विकास की योजनाओं पर खर्च किया जाएगा।
- भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर उज्जैन में चलेंगे इलेक्ट्रिक बसें।
- एमपी में तीन नए विश्वविद्यालय खोलने का भी प्रस्ताव।
- मध्य प्रदेश के कई जिलों में 22 नए आईटीआई खोलने की तैयारी।
- हर घर नल से जल पहुंचने पर फोकस।
- स्वास्थ्य विभाग में 46000 पदों पर जल्द भर्ती।
- शिक्षा के लिए 22 हजार 600 करोड़ रुपए का प्रावधान।
- लोगों की सेहत के सुधार के लिए स्वास्थ्य के लिए 21 हजार 144 करोड़ रुपए।
- वन और पर्यावरण 4 हजार 725 करोड़ रुपए।

संसद सत्र में विपक्ष के नेताओं के बीच दिखाई दिया तालमेल, राहुल-अखिलेश में दिखी केमिस्ट्री

नई दिल्ली।

लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आहूत संसद के विशेष सत्र का राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ आज सत्रावसान हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के चेहरे पर संसद के सत्र का जिक्र करते ही मुस्कान तैर जाती है। इस सत्र में राहुल गांधी ने एक बड़ी राजनीतिक उपलब्धि हासिल की। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें बालबुद्धि वाला और फेल बताया तो कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेताओं की धुरी बनकर उभरे हैं। सत्र के सत्रावसान के बाद सबसे अधिक चर्चा में भी राहुल गांधी और उनका 90 मिनट का लोकसभा में संबोधन है।

अखिलेश-राहुल का तालमेल रहा चर्चा में

दूसरी बड़ी चर्चा राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के बीच में बनी राजनीतिक केमिस्ट्री पर है। अखिलेश यादव ने सत्र के आरंभ होने के दिन पहले अपने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद को प्रमुखता से स्थान दिया। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अवधेश प्रसाद को पूरे सत्र के दौरान मान देकर साझा रणनीति को आगे बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में तालमेल को महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री के आज राज्यसभा में संबोधन के दौरान इसकी गहराई महसूस की गई। प्रधानमंत्री ने समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव से कहा कि वह अपने भतीजे (अखिलेश) को समझाएं।

घायलों से मिले योगी...किसी को बख्शा नहीं जाएगा

हाथरस, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को हाथरस पहुँच कर भगदड़ वाली घटना के स्थल का जायजा लेकर घायलों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी ने हाथरस पहुँचते ही वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा भी की। बता दें कि सीएम ने घटना की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (आगरा) और अलीगढ़ मंडल आयुक्त की एक टीम गठित की है। टीम को जांच रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर सौंपनी है। योगी ने कहा था कि हमारी सरकार घटना की तह में जाकर साजिश कर्ताओं और जिम्मेदारों को उचित सजा देने का काम करेगी। राज्य सरकार पूरी घटना की जांच करा रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार मामले में पहले से संवेदनशील है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।

इस बीच, सत्संग के दौरान हुई भगदड़ के मामले में पुलिस ने 'मुख्य सेवादार और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने मुख्य सेवादार देवप्रकाश मधुकर और अन्य सेवादारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

रिपोर्ट में कहा गया, आयोजकों ने पिछले कार्यक्रमों में पहुंची लाखों लोगों की भीड़ की स्थिति को छिपाकर इस बार 80 हजार अनुयायियों के इकट्ठा होने की बात प्रशासन से कही थी। इसके अनुसार ही सुरक्षा की व्यवस्था की थी लेकिन सत्संग में ढाई लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई। आरोप लगाया गया, सत्संग के मुख्य प्रवचनकर्ता सूरजपाल उर्फ 'भोले बाबा' के प्रवचन के बाद वह अपनी गाड़ी में सवार होकर आयोजन स्थल से निकल रहे थे, तभी अनुयायियों ने उनकी गाड़ी के मार्ग से धूल समेटना शुरू किया। इस दौरान लाखों की भीड़ के दबाव के कारण कुछ लोग कुचल गए। इसमें कहा गया, भीड़ को आयोजन समिति और सेवादारों ने जबरन रोक दिया जिसकी वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता गया और महिलाएं, बच्चे तथा पुरुष उसमें दबते-कुचलते चले गए। शिकायत में आरोप लगाया गया, मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घायल तथा बेहोश लोगों को अस्पताल पहुंचाया लेकिन आयोजनकर्ताओं तथा सेवादारों ने कोई सहयोग नहीं किया।

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट का सीबीआई को नोटिस

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने सीबीआई को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। केजरीवाल की ओर से सोमवार को याचिका दाखिल की गई थी। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत उनको 3 दिन के लिए सीबीआई की रिमांड पर भेजा गया था। फिलहाल केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है।

झारखंड के मुख्यमंत्री ने दिया इस्तीफ़ा

नई दिल्ली, एजेंसी।

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ़्तार कर लिया था। उसके बाद चंपई सोरेन को झारखंड का सीएम बनाया गया था। फरवरी में चंपई सोरेन ने ये पद संभाला था।

अब हेमंत सोरेन को बेल मिल गई है। वो बाहर आ गए हैं और तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन के विधायकों के बीच सर्वसम्मति के बाद तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में वापसी कर सकते हैं।

सूत्रों ने कहा कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में दो फरवरी को शपथ लेने वाले चंपई सोरेन ने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। झारखंड में इस साल नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित है।

अगर हेमंत पद की शपथ लेते हैं, तो वो झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। क़रीब पांच महीने जेल में काटने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें ज़मानत दे दी थी और बीती 28 जून को उन्हें रिहा कर दिया गया था।

पुलिस की गिरफ्त में सेना का भगोड़ा, तीन युवकों से ठगे 29 लाख रुपये

पुणे।

भारतीय सेना के खुफिया विभाग और पुणे पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर सेना के एक भगोड़े को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों का कहना है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति ने तीन युवाओं को सैना के अस्पताल में नौकरी दिलाने के नाम पर 29 लाख रुपये ठगे थे। आरोपी का नाम संदीप गौरव बताया गया है। उसने वर्ष 2020 में कोल्हापुर के तीन युवकों को सेना के अस्पताल में नौकरी दिलाने का झांसा दिया था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने तीनों युवकों को फर्जी नियुक्ति पत्र भी थमा दिए थे।

बायु सेना की युद्ध क्षमता में होगी वृद्धी - वायु सेना प्रमुख वीआर चौधरी

हैदराबाद, एजेंसी।

वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि हथियार प्रणाली स?कूल के निर्माण के साथ, जमीन आधारित और विशेषज्ञ हथियार प्रणालियों के संचालक एक मंच पर आ जाएंगे, जिससे भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उन्होंने प्रशिक्षकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वे इस एक नवगठित शाखा में अग्रणी है। इस कारण वे ऐसे स्तंभ हैं जिन पर परिकल्पित प्रशिक्षण व्यवस्था की पूरी जिम?मेदारी है। इससे वायु सेना सुदृढ़ होगी। स्कूल के संस्थापक सदस्यों की प्रशंसा करते हुए, वायु सेना प्रमुख ने सभी कर्मियों से देश में हथियार प्रणालियों के प्रशिक्षण के लिए स्कूल को एक नोडल केंद्र के रूप में स्थापित करने का आग्रह किया।

वायु सेना प्रमुख (सीएएस) एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने हैदराबाद के एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल (डब्ल्यूएसएस) का उद्घाटन किया। इसके साथ ही भारतीय वायु सेना (आईएएफ) के इतिहास में एक नया अध्याय का शुभारंभ हुआ है। वायु सेना प्रमुख (सीएएस) ने 08 अक्टूबर, 2022 वायु सेना दिवस परेड समारोह के दौरान हथियार प्रणाली स?कूल के गठन की घोषणा की थी। वर्ष 2022 में भारतीय वायुसेना में अधिकारियों की एक नई इकाई हथियार प्रणाली

स?कूल (डब्ल्यूएसएस) को स?वीकृति देने के बाद इसकी शुरूआत हुई। भारतीय वायु सेना को भविष्योन्मुख बल के रूप में पुनः व्यवस्थित करने और समयानुसार परिवर्तित करने के उद्देश्य से, इस नए प्रशिक्षण प्रतिष्ठान का गठन किया गया है। सामान्य रूप से सशस्त्र बलों और विशेष रूप से भारतीय वायु सेना के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

वायु सेना प्रमुख का स्वागत हथियार प्रणाली स्कूल के कमांडेंट एयर वाइस मार्शल प्रेमकुमार कृष्णस्वामी ने किया। उद्घाटन समारोह में एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, प्रशिक्षण कमान और भारतीय वायुसेना के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जिनमें एयर फोर्स अकादमी के कमांडेंट, कॉलेज ऑफ एयर वारफेयर के कमांडेंट, एयर फोर्स स्टेशन (हकीमपेट) के एयर ऑफिस कमांडिंग, और एयर फोर्स स्टेशन बेगमपेट के स्टेशन कमांडर शामिल थे। हथियार प्रणाली शाखा (डब्ल्यूएसएस) प्रकृति के अनुकूल प्रभाव आधारित प्रशिक्षण प्रदान करेगा और भारतीय वायु सेना (आईएएफ) की आवश्यकताओं के अनुरूप नवगठित शाखा के अधिकारियों को तैयार करेगा। हथियार प्रणाली शाखा के फ्लाइट कैडेट इस संस्थान में अपने दूसरे सेमेस्टर का प्रशिक्षण लेंगे। नई शाखा में सुखोई-30 एमकेआई और सी-130जे, हवाई प्लेटफार्मों में हथियारों और प्रणालियों को संचालित करने के लिए फ्लाइंग स्ट्रीम, दूर से संचालित विमानों को संचालित करने के लिए रिमोट स्ट्रीम, सतह से हवा और सतह से सतह पर मार करने वाली हथियार प्रणालियों के लिए मिशन कमांडर, ऑपरेटर और अंतरिक्ष-आधारित खुफिया और इमेजरी को संभालने के लिए इंटेलिजेंस स्ट्रीम चार धाराएँ शामिल होंगी।

जोखिमों से निपटने को वैश्विक प्रयास जरूरी- अश्विनी वैष्णव

नई दिल्ली।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि एआई से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए वैश्विक प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुनिया में सभी देश और समाज के लोग एआई से पैदा होने वाले नए खतरों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। लेकिन, चुनौतियों का प्रभावी समाधान केवल सामूहिक वैश्विक प्रयासों से ही संभव है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री ने कहा कि कि इंडिया एआई मिशन जिसे इस साल की शुरुआत में मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी, उसे अगले दो से तीन महीने में पेश किया जाएगा। वहीं ग्लोबल इंडिया एआई समिट को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में एआई के लिए एक पूरा पैकेज तैयार किया जा रहा है। एक विशेषज्ञ दल इसकी नींव और स्तंभों को स्थापित करने पर काम कर रहा है। दो से तीन महीने के भीतर इसे सबके सामने पेश कर दिया जाएगा।

इस साल कैबिनेट ने 10,300 करोड़ दी है मंजूरी

दरअसल में मंत्रिमंडल ने इस वर्ष मार्च में इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपये से अधिक के आवंटन को मंजूरी दी थी। इसे भारत के एआई परिवेश को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। इसके तहत अगले पांच वर्ष में किए जाने वाले वित्तीय निवेश का मकसद कई घटकों को बढ़ावा देना है, जिनमें इंडिया एआई कंप्यूट कैपेसिटी, इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर, इंडिया एआई डाटासेट प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लिकेशन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग और सुरक्षित तथा विश्वसनीय एआई पहल शामिल हैं।

लटकती लाशों को लेकर बड़ा खुलासा

माही की गूंज, अलीराजपुर।

अलीराजपुर पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है। इसकी वजह यहां दिल्ली के बुराड़ी जैसी घटना का होना है। बुराड़ी की तरह यहां भी परिवार के सभी सदस्य फंदे से लटके मिले। पुलिस ने सभी शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार, पांच सदस्यों का परिवार कर्ज में डूबा हुआ था जिसकी वजह से हो सकता है उन्होंने आत्महत्या कर ली।

टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, 'जांच के दौरान पता चला कि राकेश के पिता जगर सिंह पर विवाद के बाद हमला किया गया था। ऐसा शक है कि परिवार को उनके इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ा था और जब वे पैसे नहीं चुका पाए तो उन्होंने अपनी दो एकड़ जमीन 45 हजार रुपये में गिरवी रख दी।' एसपी राजेश व्यास ने कहा, 'हालांकि, यह पता चला है कि उनका इलाज आयुष्मान योजना के तहत हुआ था।'

एसपी ने कहा कि परिवार के सदस्यों पर काफी कर्ज था, लेकिन उन्होंने कर्ज क्यों लिया, इसका कारण फिलहाल पता नहीं चला है। अलीराजपुर जिले के गुनेरी पंचायत के रौड़ी गांव में सोमवार सुबह 30 साल के किसान राकेश, उनकी 28 साल की पत्नी ललिता, सात साल के बेटे प्रकाश और 5 साल के बेटे अक्षय का शव फंदे से लटका मिला और 9 साल की बेटी लक्ष्मी का शव घर के अंदर फर्श पर पड़ा था, उसके गले में भी फंदा था।

मामले का खुलासा तब हुआ जब राकेश के चाचा किसी काम से उनके घर पहुंचे। जब किसी ने गेट नहीं खोला तो उन्होंने अंदर झांककर देखा। घर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। सीएमएचओ डॉ. प्रकाश ढोके ने बताया कि पांच डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया और पाया कि सभी की मौत दम घुटने से हुई है। शवों पर चोट के कोई निशान नहीं हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि राकेश ने अपनी पत्नी और तीन बच्चों की हत्या कर खुद भी फांसी लगा ली या फिर उसकी पत्नी भी इस अपराध में शामिल थी।

राकेश टीन शेड वाले मकान में रहता था, जबकि उसके पिता पास में ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकान में रहते थे। गांव के सरपंच ओमप्रकाश रावत ने बताया कि परिवार का किसी से कोई विवाद नहीं था और वे बहुत खुशमिजाज थे। गांव में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वे इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। इस केस ने 6 साल पहले दिल्ली के बुराड़ी केस की यादें लोगों के जेहन में ताजा कर दी हैं।

संसद द्वारा पारित तीन नए नियमों पर प्रशिक्षण आयोजित

माही की गूंज, झाबुआ। कलेक्टर नेहा मीना द्वारा जिला पंचायत के नवीन सभा कक्ष में संसद द्वारा पारित तीन नए नियमों पर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.एल.कुर्वे द्वारा संसद द्वारा पारित कानून जिनमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक संहिता 2023 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान अपर कलेक्टर एस.एस. मुजाल्दा, संयुक्त कलेक्टर सत्यनारायण दर्रो, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अन्य राजस्व अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

इमरती देवी ने जज के सामने पुलिस पर उठाया सवाल, बोलीं- आम आदमी की नहीं सुनते

ग्वालियर।

अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री इमरती देवी एक बार फिर से चर्चा में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस पर निशाना साधती नजर आ रही हैं। इस दौरान वहां पर सिविल कोर्ट के न्यायाधीश संजय गुप्ता भी मौजूद थे।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री इमरती देवी पुलिस प्रशासन पर तल्ख टिप्पणियां करती हुईं नजर आ रही हैं। उन्होंने यह तक कह डाला कि थाने में जाने पर पुलिस कहती है कि तहकीकात करेंगे, लेकिन तहकीकात तो होती ही नहीं है। हम जैसे लोग अगर पहुंच जाए तो फिर तत्काल तहकीकात शुरू कर दी जाती है, लेकिन आम आदमी की सुनवाई नहीं होती।

सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सिटी थाने में आयोजित नए कानून के जागरुकता कार्यक्रम का बताया जा रहा है। कार्यक्रम में न्यायाधीश संजय गुप्ता भी मौजूद थे। अपने भाषण के दौरान इमरती देवी कह रही हैं कि पुलिस कहती है कि तहकीकात करेंगे, लेकिन थाने में तो तहकीकात होती ही नहीं है। उन्होंने कहा कि हम जैसे लोग अगर आ जाएं तो फटाक एफआईआर और किसी भी धाराओं में केस दर्ज कर ली जाती है। लेकिन जिनके पास हम जैसे लोग नहीं है उनकी न अस्पताल में सुनवाई होती है और न ही थाने में।

अपने भाषण में इमरती देवी ने कहा कि वह कभी झूठ नहीं बोलतीं। उनके क्षेत्र में 6 थाने हैं। उन्होंने कभी किसी के लिए दरोगा, टीआई, एसडीओपी या किसी पुलिस अधिकारी को फोन नहीं किया। अग कोई ऐसा बता दे तो वह राजनीति छोड़ देंगी। इसलिए उनका निवेदन है जो भी एफआईआर पुलिस दर्ज करे, उसे न्याय के साथ करे।

अपने बेवाक अंदाज में उन्होंने जज साहब तक को नहीं छोड़ा। इमरती देवी बोलीं कि इन थानों से बड़े-बड़े केसों में लोग फंसकर रह जाते हैं। पुलिस नहीं तो आप ही उन्हें न्याय दें। इसके साथ ही इमरती देवी ने नए कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 01 जुलाई 2024 को आदेश पारित

माही की गूंज, झाबुआ। अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग झाबुआ द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत 01 जुलाई 2024 को पारित कानून के संबंध में आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टोरेट परिसर में आये दिन कतिपय व्यक्तियों, संस्था, अन्य संगठनों के द्वारा प्रदर्शन, ज्ञापन के दौरान कानून व्यवस्था एवं लोक व्यवस्था भंग कर गडबड़ी फैलाने एवं आग्नेय शस्त्र, घातक हथियार एवं विस्फोटक पदार्थ का दुरूपयोग किए जाने की प्रबल आशंका रहती है और असामाजिक तत्वों द्वारा भी आग्नेय शस्त्र, एवं विस्फोटक पदार्थ का उपयोग कर बलवा, अशांति, लूटमार आदि करने की आशंका भी रहती है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से शासकीय कार्य एवं लोक प्रशांति बनाए रखने हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुभाग झाबुआ सत्यनारायण दर्रो द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टोरेट परिसर झाबुआ में सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धरना प्रदर्शन, बिना सूचना के ज्ञापन आदि प्रस्तुत नहीं करेगें, किसी भी प्रकार का आग्नेयशस्त्र अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे। (लायसेंस परमिट के सत्यापन को छोड़कर), कोई भी घातक हथियार अपने साथ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति विस्फोट पदार्थ साथ लेकर नहीं चलेगा, कोई भी व्यक्ति, संगठन, राजनैतिक दल, प्रत्याशी बिना पूर्वानुमति के न तो आम सभा करेगा, न कोई रैली निकालेगा और न ही जुलूस का आयोजन करेगा। यह कानून व्यवस्था के कार्यों में संलग्न लोकसेवकों, ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल तथा विशेष रूप से प्राधिकृत व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा। यह कानून सर्वसाधारण को संबोधित है एवं समयाभाव के कारण इसकी तामिली एवं सुनवाई सम्यक समय में करना संभव नहीं है। यह आदेश धारा-163 की उपधारा-2 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया। यह आदेश अनुभाग झाबुआ ने अस्थाई रूप से भ्रमण एवं निवास करने वाले व्यक्तियों पर यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

1 जुलाई से लागू हुए नए कानून की जानकारी आम नागरिकों को दी गई

माही की गूंज, आम्बुआ।

वर्षों पूर्व अंग्रेजों के शासन काल में बने पुराने कानूनों को शासन द्वारा नवीनता प्रदान कर नऐ कानून 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। जिसकी विधिवत जानकारी नागरिकों को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रदान की गई।

आम्बुआ थाना प्रभारी ने 1 जुलाई से लागू हुए नवीन कानून के विषय में आम नागरिकों एवं पत्रकारों को जानकारी प्रदान करते विभिन्न लोक हितों के विषय में बताया। थाना प्रभारी योगेंद्र मंडलोई ने उपस्थित जन मानस को पुराने कानून के स्थान पर शासन द्वारा लाऐ गए नए कानूनों की जानकारी प्रदान की गई। जिसमें भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियो की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम पटेल एवं पूर्व न्यायाधीश भारतसिंह रावत (पटेल) ने अपने अनुभव साझा करते हुए नवीन कानूनों को आम जनता के हितों में तथा कानूनों का सरलीकरण बताया। उन्होंने इन कानून को जनमानस तक पहुंचाने हेतु पत्रकारों का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि अब दंड का स्वरूप बदलेगा जो सजा जेल के अंदर व्यतीत होती थी अब नवीन व्यवस्था में न्यायालय सामुदायिक सजा भी सुना सकेंगे। इसके तहत अपराधियों को समाज सेवा आदि की सजा दी जा सकेगी जिसमें अपराधी समाज में सेवा कर अपने आप में सुधार लाकर जीवन सुखमय बना सकेंगे कार्यक्रम में ग्राम टेमाची सरपंच नानसिंह कनेश, ग्राम कोटबू सरपंच बबलू पटेल ने ग्रामीण भाषा में कानून की जानकारी प्रदान की, भाजपा मंडल अध्यक्ष ने भी संबोधित करते हुए हाट बाजार में प्रचार प्रसार करने की बात कही। इसी के साथ-साथ शिक्षण संस्था तथा ग्राम पंचायत में होने वाली ग्राम सभाओं आदि में भी ग्रामीणों को नए कानूनों की जानकारी हेतु सुझाव भी दिए गए। ग्राम बोरझाड़ के युवा निकुंज राज गोयल ने निशुल्क कानूनी सहायता तथा नए कानून के कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डाला कार्यक्रम में सरपंच रमेश रावत, भोरदू पटेल करम सिंह, कमलसिंह कनेश, वरिष्ठ पत्रकार जगराम विश्वकर्मा, साजिद शेख, पूर्व विधायक प्रतिनिधि अमान पठान, मुस्लिम सदर चांद मोहम्मद मकरानी, रामचंद्र माहेश्वरी, थानसिंह भयडिया (उप सरपंच) मुस्तू बोहरा, रूमसिंह भूरिया आदि अनेक नागरिक सरपंच पंच चौकीदार आदि उपस्थित रहे।

युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष ने विद्यार्थियों की समस्या को लेकर रखी मांग

माही की गूंज, अलीराजपुर।

युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष और समाजसेवी तरुण मंडलोई ने अलीराजपुर कलेक्टर डॉ. अभय अरविंद बेडेकर से आदीवासी छात्र-छात्राओं की समस्या को मद्देनजर रखते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से मांग रखी। तरुण मंडलोई का कहना है कि, अलीराजपुर जेसे आदिवासी बाहुल्य जिले में जहा शिक्षा का स्तर काफी कम है, वही नए शैक्षणिक सत्र में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

ज्ञात हो कि, हमारे जिले में जागरूकता और साक्षरता की कमी के कारण अधिकांश परिवारजनों के पास उचित दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, स्थाई जाती प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज या तो उपलब्ध नहीं है, या बनवाए नही है। ऐसी स्थिति में कोई भी छात्र- छात्रा इनके अभाव में प्रवेश से वंचित न रह जाए। तरुण मंडलोई ने मांग की है कि, यह सुनिश्चित किया जाना बहुत ही जरूरी है की किसी भी छात्र का भविष्य इस स्थिति में खराब ना हों। मंडलोई ने अलीराजपुर कलेक्टर से सोशल मीडिया के माध्यम से निवेदन किया है की,उक्त दस्तावेज संबंधी समस्या के संबंध में सहायक आयुक्त जनजाति कार्यविभाग को उचित निर्देश देकर समस्त माध्यमिक और हाईस्कूल के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाए कि कोई भी छात्र-छात्रा विद्यालय में प्रवेश से दस्तावेजों के अभाव में वंचित ना रहे। छात्र-छात्राओ को प्रवेश देकर उनके अपूर्ण दस्तवेजों के लिये अतिरिक्त समय दिया जायें। प्रवेश के संबंध में दस्तावेजो के अभाव में यदि कोई भी छात्र-छात्रा वंचित रहता है तो संबंधित प्राचार्य - प्राचार्या या फिर संबंधित पर अनुशासनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

मानवीय संकट बढ़ाती परमाणु अस्त्र होड़

इस माह की चर्चाओं के केंद्र में मुख्य विषय प्रलयंकारी परमाणु हथियार और संकट में पड़े वैश्विक सुरक्षा तंत्र रहे। गत 17 जून को दो अहम रिपोर्टें एक ही दिन जारी हुईं्द एक है, आईसीएएन (इंटरनेशनल कैम्पेन टू एबोलिश न्यूक्लियर वैपन्स) की और दूसरी है सिपरी (स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट) की। इनके निष्कर्ष कष्टकारी और निराश करने वाले हैं।

आईसीएएन रिपोर्ट बताती है कि एन-9 अर्थात? परमाणु शक्ति संपन्न नौ राष्ट्रों (अमेरिका, यूके, रूस, चीन, फ्रांस, भारत, इस्राइल, पाकिस्तान और उत्तर कोरिया) ने अपने-अपने आणविक शस्त्रागारों के आधुनिकीकरण और विस्तार कार्यक्रम पर 91 बिलियन डॉलर की राशि खर्च की है। इस बारे में सबका तर्क एक समान है यानी 'दूसरों से परमाणु खतरे' का वास्ता देते हुए, अपने अंदर गहरे पैठी सामरिक 'असुरक्षा की भावना' का तुष्टीकरण है।

अनुमान को सिद्ध करते हुए, सबसे अधिक धन खर्च वालों में चोटी के तीन मुल्कों में पहले पायदान पर अमेरिका है (51.5 बिलियन डॉलर)- जो कि विश्वभर में परमाणु हथियार संबंधित कुल व्यय का आधे से अधिक है, दूसरे नंबर पर चीन (11.8 बिलियन) और तृतीय पर रूस (8.3 बिलियन) है। आईसीएएन की निदेशक मेलिसा पार्के का कहना है कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का इस मद में सकल खर्च प्रति सेकंड 2,898 डॉलर बैठता है और यह सम्मिलित व्यय संपूर्ण दुनिया से भुखमरी खत्म करने को जितना पैसा चाहिए, उससे अधिक है। उन्होंने आगे कहा- 'एक मिनट में जितना खर्च परमाणु हथियारों पर होता है, उतने में 10 लाख पौधे रोपे जा सकते हैं।'

यहां पर रोपे जाने वाले पौधों की संख्या का संदर्भ वैश्विक ताप सूचकांक में निरंतर बढ़ोतरी और पर्यावरणीय बदलावों से पैदा हुए अतिशय मौसम के संदर्भ में प्रासंगिक है, किंतु इस मुद्दे पर संसार की प्रतिक्रिया लचर और निष्प्रभावी किस्म की है। भारत इन दिनों झुलसा देने वाली गर्मी झेल रहा है, तिस पर इसका पेड़ और मनुष्य का अनुपात भयावह रूप से बहुत कम है, और भारत विश्व के सबसे अधिक प्रभावित बड़े देशों में एक है (कुल भूभाग और जनसंख्या के लिहाज से)। यह भू-भौतिक प्रवृत्ति जल्द ही विश्व के सभी मनुष्यों की सुरक्षा के लिए गंभीरतम खतरा बनने जा रही है। हज करने गए लोगों की झुलसाती गर्मी से संबंधित हालिया मौतें इसका साक्षात उदाहरण हैं।

सिपरी की वार्षिक पत्रिका-2024 वह बृहद प्रकाशन है जो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, शस्त्र एवं तकनीक, सैन्य व्यय, शस्त्र उत्पादन, शस्त्र-व्यापार, हथियारबंद संघर्ष और युद्ध प्रबंधन के अलावा रिवायती, परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों पर नियंत्रण को लेकर प्रयासों का अवलोकन प्रस्तुत करता है। लगभग सौ पन्नों का परमाणु अध्याय पिछले साल परमाणु क्षेत्र में हुए नवीनतम विकास और चलन का बहुमूल्य सार प्रस्तुत करता है। लेखक हैन्स क्रिसटेंसेन और मैट कोर्डा के परिश्रम की तारीफ करनी करनी बनती है कि उन्होंने इस गोपनीय क्षेत्र की अंदरूनी जानकारी बहुत मेहनत से खोद निकाली है, जबकि इस विषय-वस्तु पर अमूमन तथ्यों की जगह भ्रामक जानकारी एवं सूचनाएं और राजनीतिक लफ्फाजी का बोलबाला रहता है।

सिपरी आणविक सर्वे का मुख्य निष्कर्ष यह है कि परमाणु हथियारों की किस्मों और संख्या में वृद्धि हुई है। सभी परमाणु शक्ति संपन्न मुल्कों ने अपनी 'प्रतिरोधक आणविक' क्षमता पर निर्भरता बढ़ाई है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह करने से मूल राष्ट्रीय हित सुरक्षित होते हैं। इसका नवीनतम उदाहरण रूस-यूक्रेन युद्ध है, जब रूस ने अमेरिका नीत नाटो को

परमाणु अस्त्र प्रयोग की धमकी देते हुए अपनी ओर से 'रेड लाइन' खींच दी, बदले में, नाटो और अमेरिका ने भी कहा कि वे भी अपनी तमाम जवाबी परमाणु तैयारियों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं।

सिपरी आणविक अवलोकन संकेत देता है कि 2024 के शुरुआती दिनों में, नौ परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों के पास कुल मिलाकर लगभग 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 9,585 के बारे में माना जाता है कि इस्तेमाल के लिए तत्काल तैयार हैं। कयास है कि 3,904 आणविक आयुध कार्यकारी बलों के साथ तैनात हैं और इनमें भी लगभग 2100 को उच्च संचालन सतर्कता श्रेणी में रखा गया हैद्द यह संख्या पिछले साल के मुकाबले 100 अधिक है।

जहां एक ओर अमेरिका और रूस के परमाणु हथियारों का सम्मिलित हिस्सा अभी भी विश्व के सकल आणविक शस्त्रागारों का 88 प्रतिशत है वहीं चीन को लेकर सिपरी का आंकड़ा चौंकाने वाला है, जनवरी, 2023 में उसके पास 410 परमाणु अस्त्र थे जो जनवरी, 2024 में बढ़कर 500 हो गए और इनकी संख्या आगे और बढ़ने की उम्मीद है। यह भी कहा कि चीन अगले एक दशक तक अपने परमाणु शस्त्रागार का काफी आधुनिकीकरण और विस्तार करने की प्रक्रिया में लगा रहेगा और कुछ अनुमानों के मुताबिक इस अवधि में चीन भी रूस एवं अमेरिका जितनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलेस्टिक मिसाइलें तैनात करने का मंसूबा रखता है।

चूंकि चीन की अमेरिका से होड़ है, उसके आणविक हथियारों की तैनाती (जो वर्तमान में 24 है) में स्पष्ट दिखाई देने वाली बढ़ोतरी का बहुत ज्यादा असर दक्षिण एशिया की रणनीतिक संतुलन स्थिरता पर पड़ेगा, जो कि भारत के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।

शीत युद्ध के दौरान, अमेरिका एवं उसके सहयोगियों और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच परमाणु मिसाइलों की गिनती बढ़ाने की दौड़ 1945 से 1991 तक जमकर चली। साल 1962 के 'क्यूबा मिसाइल संकट' प्रसंग से पैदा हुए डर के बाद, इन दोनों पक्षों ने अपनी रक्षार्थ एक भरोसेमंद, मजबूत आणविक प्रतिरोध प्रणाली कायम करने की ओर कदम बढ़ाए, जिसकी वजह से आगे चलकर शस्त्र नियंत्रण संधि और 'मैड' नामक (म्युचुअली एशोर्ड डिस्ट्रक्शन) सिद्धांत उपजा और यह 'मैड' शब्द विनाशकारी व्यंग्यवाद का द्योतक भी है।

फरवरी, 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से, विश्व दो प्रतिस्पर्धी परमाणु हथियार युक्त खेमों में बंटता चला गया, एक तरफ अमेरिका के नेतृत्व वाला सैन्य गठबंधन है (जिसमें यूके और फ्रांस हैं) तो दूसरी तरफ रूस-चीन की जोड़ी है, जिसके साथ कनिष्ठ सहयोगी के तौर पर उत्तर कोरिया है। परमाणु शक्ति संपन्न अन्य तीन राष्ट्रद्द भारत, पाकिस्तान और इस्राइल द्द ऊपरी तौर पर भले ही गुट-निरपेक्ष दिखाई देते हों किंतु उनका भू-राजनीतिक उन्मुखता से झुकाव स्वयं सिद्ध है।

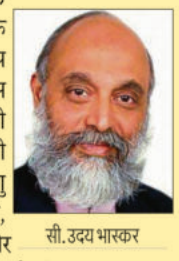

सी.उदय भास्कर

लेख के शुरू में जिस निराशा का जिक्र है उसके पीछे वजह यह है कि 2022 से संसार यथेष्ट 'आणविक प्रतिरोध' क्षमता बनाए रखने वाली नीति से हटकर अब जिस तरह बेलगाम और बेपरवाह होड़ में लगा है। मुख्य शक्तियों के बीच विगत में सामरिक मुद्दों को लेकर जो संचार व्यवस्था और सुव्यवस्थित शस्त्र नियंत्रण एवं संयम बनाए रखने वाली परस्पर समझ थी, वह भी लगातार घटती जा रही है।

वर्तमान में अमेरिका में तीव्र घरेलू सामाजिक-राजनीतिक मंथन चला हुआ है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने की संभावना अधिक है। जहां रूस, चाहे कुछ भी हो जाए, यूक्रेन पर अपनी पकड़ बनाए रखने को कटिबद्ध है, वहीं चीन द्वारा अपने इलाकाई दावों को लेकर झगड़ालू रुख कायम रखने से क्षेत्रीय शांति भंगुर बनी हुई है। यह एक अपशकुन है। आईसीएएन और सिपरी की रिपोर्टें बेशक इस बंजर परिदृश्य पर उद्देश्यपूर्ण ढंग से रोशनी डालती हैं, लेकिन चिंताजनक वास्तविकता यह है कि सुरंग के अंत में प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा।

माही तट पर घाट के लिए परेशान हो रहे क्षेत्रवासियसों को मिली बड़ी राहत

राजनीतिक असफलता के चलते लाखों के निजी खर्च से तैयार किया गया घाट, अब दुर्घटना का भय होगा कम

माही की गूंज , पेटलावद।

माही माता के नाम से प्रसिद्ध माही नदी पर एक अनूठी पहल से क्षेत्र भर और दूर-दूर से माही माता के दर्शन के लिए आने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिली है। यहां झाबुआ-रतलाम की सीमा पर स्थित माही नदी की एक ओर झाबुआ जिले की सीमा तो दूसरी और रतलाम जिले की सीमा लगती है, लेकिन दोनों और घाट नहीं होने से श्रद्धालुओं को नदी तक पहुँचने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। तो कई बार इस प्रयास में लोग दुर्घटना का शिकार भी हो जाते है। यहां दोनों ओर के क्षेत्रवासियों द्वारा लंबे समय से सुव्यवस्थित घाट की मांग की जा रही है।

चर्चाओं के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री, पेटलावद विधायक निर्मला भूरिया पेटलावद क्षेत्र की ओर घाट बनाने का आश्वासन दे चुके है, लेकिन घाट के लिए फिलहाल कोई प्रशासनिक चहल-पहल नहीं देखी गई। वहीं दूसरी और रतलाम जिले की सीमा की ओर पढ़ने वाले घाट को लेकर भी क्षेत्र के राजनीतिक प्रयास शून्य ही रहे। ऐसे में ग्राम रानीसिंग के कुछ लोगों ने स्वयं के व्यव से इस घाट के निर्माण का बीड़ा उठाया और घाट तैयार किया। यहां माही नदी के ऊपर रानीसिंग का मुक्ति धाम भी बना हुआ है। साथ ही बड़ी संख्या में मन्नतधारी यहां पहुँच कर मन्नत उतारते और स्नान करते है। ग्राम रानीसिंग के बलवंत सिंह राठौर ने घाट निर्माण का बीड़ा उठाया। संदीप मालीवाड़, अम्बालाल गरवाल और हीरालाल गुर्जर से सहयोग लेकर उक्त घाट तैयार करवाया। घाट निर्माण में विशेष भूमिका रखने वाले बलवंतसिंह राठौर ने बताया कि वर्षों से क्षेत्र के लोग इस घाट को लेकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन कोई सफलता

नहीं मिली। माही माता के आदेश से इस घाट को बनाने का मन मे विचार आया और कुछ लोगों से चर्चा कर इसका निर्माण शुरू किया और घाट तैयार किया। घाट निर्माण से यहां मुक्ति धाम पर अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों सहित यहां माता जी के दर्शन और पूजा पाठ के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी।

नदी को सुंदर बनाए जाने के होना चाहिए प्रयास, राजनीतिक असफलता के चलते क्षतिग्रस्त पुलिया भी नहीं हो पा रहा सही

देश भर में जाने जाना वाला नाम 'माही नदी' से आधा गुजरात और राजस्थान इसके पानी से विकास की राह पर है, लेकिन मध्यप्रदेश में माही नदी की अनदेखी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार की जा रही है। पेटलावद, थांदला, रतलाम की सीमा क्षेत्र में कई ऐसे स्थान है जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु माही माता के दर्शन और अंतिम संस्कार के लिए भी दूर-दूर से पहुँचते है। इन स्थानों को आज तक चिंहित कर व्यवस्था और सुविधा नहीं की गई। जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं झाबुआ-रतलाम की सीमा को जोड़ने वाला पुल भी दयनीय स्थिति में है। यहां पुल के दोनों ओर बनी रेलिंग पुरानी होकर जर्जर हो चुकी है और कई जगहों से टूट चुकी है। जिससे पुल पर होने वाली मामूली दुर्घटना कभी भी गम्भीर रूप ले सकती है। यहां से गुजरने वाले वाहनों को डर के साये में गुजरना पड़ता है। खास कर छोटे और दुपहियां वाहनों को जिनको भारी वाहनों को क्रॉस करते समय टूटी रेलिंग के बेहत नजदीक से गुजरना पड़ता है।

अपनी पोती वापस दिलाने बुजुर्ग ने दिया पुलिस में आवेदन

माही की गूंज, बनी। ऋषभ गुप्ता

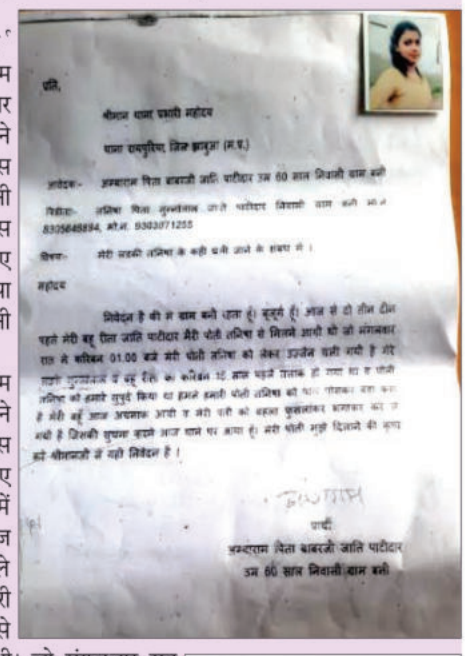

बुजुर्ग अंबाराम बाबरजी पाटीदार उम्र 60 वर्ष ने रायपुरिया पुलिस थाने में अपनी पोती को वापस दिलाने के लिए आवेदन दिया और अपनी व्यथा बताई।

अंबाराम पिता बाबर जी ने रायपुरिया पुलिस थाने में दिए आवेदन में बताया कि आज से दो -तीन पहले मेरी बहु रीता मेरी पोती तनीषा से मिलने आई थी। जो मंगलवार रात करीब 1 बजे मेरी पोती तनीषा को लेकर उज्जैन चली गई है। मेरे लड़के मुन्नालाल पाटीदार की शादी रीता से हुई थी, मगर कारण वर्ष वह संबंध टूट गया और तलाक हो गया। पोती तनीषा को हमारे सुपुर्द किया गया था। हमने हमारी पोती को पाल पोस कर बड़ा किया है। तलाक हुए भी 15 वर्ष हो गए है। मगर रीता मुन्नालाल की पूर्व पत्नी अचानक मेरे घर पर आई और मेरी पोती तनीषा पाटीदार को बहला फुसलाकर अपने साथ लेकर उज्जैन चली गई है। अंबाराम का कहना है कि मैने मेरी पोती को पाल पोसकर बड़ा किया है और मेरे घर की वारिश भी वही है। मेरे पास खेती-बाड़ी भी पर्याप्त है, ऐसे में रीता से मुझे मेरी पोती तनीषा वापस दिलाई जाए।

चींटी कण के लिए, मच्छर लहू के लिए, मनुष्य धन के लिए अनादि काल से दौड़ रहा है-संत अजीत प्रभा

माही की गूंज, पेटलावद।

पेटलावद में सागर संप्रदाय के आचार्य श्री पूज्य नयचंद्र जी महाराज साहब ठाणा 20 विराजमान है। इनके शिष्य गण प्रति दिन स्थानक भवन में प्रवचन प्रदान कर रहे हैं। पूज्य ऋषभ चंद्र जी ने कहा हमें मनुष्य भव जिनवाणी सुनने, उस पर श्रद्धा कर उसे आचरण में उतारने के लिए के समय मिल गया है। संसार की दौड़ को मोड़ना है एवं दिशा बदलना है व मोक्ष को पाना है। गुरुदेव ने पेटलावद संघ की सेवा भावना की भी प्रशंसा की। सहस्त्र अवधानी गणीवर्य संत अजीत चंद्र जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान ने अपनी देशना में अधिकतर प्राणियों को बोध प्राप्त करने का संदेश दिया है। जिसका आशय होता है अनुभव के आधार पर सही समझ को प्राप्त करना। पशु-पक्षी सभी उठकर दाना पानी के लिए अपने स्थान से निकलते है, चींटी कण के लिए, मच्छर लहू के लिए, मनुष्य धन के लिए अनादि काल से दौड़ रहा है। पशु-पक्षी तो सुबह जाकर शाम को लौट आते हैं पर मनुष्य तो अतिरिक्त व्यवस्था में लगा रहता है। जबकि परिजन धन संपत्ति सभी बंधन है मिथ्या है। भगवान के ज्ञान का अजनं लगते ही मिथ्या का पर्दा हटेगा। आत्मा को पहचानेंगे और सही लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। 02 जुलाई को आचार्य श्री उमेश मुनि जी की मासिक पुण्यतिथि होने के अवसर पर नवयूवक मंडल द्वारा नवकार मंत्र का जाप किया गया एवं अणु चालीसा का पाठ भी किया गया। संत चंद प्रभ जी ने कहा आहार, आवास, वस्त्र तीन आवश्यकता है। उसकी पूर्ति करना जरूरत है। इसमें अतिरिक्त साधन जुटाना सुविधा है। अतिरिक्त साधन जोड़ना शोक है। जैसे मकान बनाना आवश्यकता है उसमें साधन जुटाना सुविधा है पर उसमें फर्नीचर एसी टीवी आदि अतिरिक्त साधन लगाना शौक है।

जिले की समस्त संचालित उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया जाएगा

माही की गूंज, झाबुआ।

जिला आपूर्ति अधिकारी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासन मंशानुरूप जिले की समस्त शासकीय चित मूल्य दुकानों में पात्र हितग्राहियों को राशन सामग्री समुचित रूप से वितरीत हो रही है, कि पुष्टि हितग्राहियों से फिडबेक लेकर सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर से उचित मूल्य दुकानवार अपर कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, नायब तहसीलदार, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला आपूर्ति अधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के अधिकारियो की ड्युटी लगाई गई है।

समस्त अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण/जांच कर हितग्राहियों को प्राप्त राशन सामग्री वितरण के संबंध में फिडबैक लेंगें। यदि जांच कार्यवाही में पात्र हितग्राहियों को सामग्री वितरण में किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता प्रतीत होती है तो संबंधित विक्रेता पंव संस्था प्रबंधक के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित की जाएगी। जिसकी प्रतिसप्ताह आयोजित समय-सीमा बैठक में समीक्षा की जाएगी। इस हेतु समस्त विक्रेताओं को निर्देशित किया गया कि नियमित रूप से उचित मूल्य दुकान का संचालन करें तथा समस्त पात्र हितग्राहियों का ई-केवायसी प्राथमिकता से करने के निर्देश जारी किये गये है।

विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए जिला स्तरीय ''गुरुकुलम्'' योजना प्रारंभ

माही की गूंज, झाबुआ। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग द्वारा झाबुआ जैसे जनजातीय बाहुल्य जिले में अधिकांश विद्यार्थियों की शैक्षिक निर्भरता शासकीय शिक्षा सुविधाओं पर अत्यधिक हैं। साथ ही जिलें में निवासरत अधिकांश परिवार आर्थिक रूप से सशक्त भी नहीं हैं।

ऐसे में जनजातीय क्षेत्र के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर भविष्य की प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करना एक बड़ी चुनौती हैं। क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस अवसर मिलने की देर हैं। क्षेत्र की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य विभाग जिला झाबुआ ने कलेक्टर नेहा मीना के मार्गदर्शन में शासकीय हाईस्कूल एवं हायरसेकेण्डरी शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु तैयार करने के लिए जिला स्तरीय ''गुरुकुलम्'' योजना प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। गत सत्र के परीक्षा परिणाम एवं जिले से शासकीय शालाओं से एनईईटी परीक्षा में विद्यार्थियों की सफलता के आधार पर ''गुरुकुलम्'' योजना सत्र 2024-25 से प्रारंभ की जा रही हैं। योजना अंतर्गत एनईईटी परीक्षा तैयारी हेतु 50 छात्र एवं 50 छात्राओं कुल 100 विद्यार्थियों का चयन एक चयन परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इस चयन परीक्षा में कक्षा 10वीं एवं कक्षा 11वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी प्रतिभागिता करेंगे। इस चयन परीक्षा में 200 विद्यार्थियों को चयन कर उनका साक्षात्कार लिया जाएगा एवं साक्षात्कार उपरांत 100 विद्यार्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा, जिसमें 50 विद्यार्थी कक्षा 11वीं में तथा 50 विद्यार्थी कक्षा 12वीं में चयनित होंगे।

योजना अंतर्गत चयनित 100 विद्यार्थियों को छात्रावास सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी, साथ ही इन विद्यार्थियों में से चयनित बालकों को शा बालक उमावि रातीतलाई एवं बालिकाओं को शा कन्या उमावि झाबुआ में प्रवेश दिलाया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों की दैनिक दिनचर्या तैयार की जाएगी, जिसमें खेलकुद, कैरियर मार्गदर्शन, मोटिवेशनल सेशन, के साथ-साथ मेरिट आधार पर चयनित विशिष्ट शिक्षकों द्वारा सामान्य शाला समय के अतिरिक्त कक्षायें ली जाएगी, जिसमें चयनित विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करायी जाएगी। जिले की सभी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी में इस योजना के संबंध में प्राचार्य एवं शिक्षकों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया है। प्रचार प्रसार के बाद पात्र विद्यार्थियों के चयन परीक्षा हेतु आवेदन खण्ड शिक्षा अधिकारीयों के माध्यम से एकत्रित कराए गए हैं। चयन परीक्षा 07 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी। चयन परीक्षा हेतु शा. बालक उ.मा.वि. रातीतलाई झाबुआ एवं शा. कन्या उ.मा.वि. झाबुआ को परीक्षा केन्द्र बनाया हैं।

यह सर्व हारा बजट '' सबका साथ, सबका विकास'' को दर्शाता है, प्रस्तुत बजट से प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी-सुश्री निर्मला भूरिया

डॉ. मोहन यादव सरकार के बजट 2024-25 का किया अन्तर्हृदय से स्वागत

माही की गूंज, झाबुआ।

बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है। लाड़ली बहना योजना, लाड़ली लक्ष्मी योजना, बच्चों की पोषण की सुरक्षा, आंगनबाड़ियों के उन्नयन, नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व आत्मनिर्भर बनाने हेतु नवीन कार्य योजना, जेंडर बजट में बढ़ोतरी, मातृशक्ति को संबल और सम्मान प्रदान करने वाला बजट है। उक्त बात प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार के 2024-25 के बजट को जनानेन्मुखी बताते हुए व्यक्त किया।

सुश्री भूरिया ने बताया कि वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने आज प्रस्तुत बजट में 3.65 करोड़ का बजट का प्रावधान किया है। जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 46000, शिक्षा विभाग में 11 हजार टीचर्स की भर्तिया की जाएगी। सुश्री भूरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि डा. मोहन सरकार ने इस बार 3 लाख 65 हजार 67 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। सरकार ने 2024-25 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाया है। इस बजट में महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान पर मुख्य फोकस किया गया है। मोहन सरकार स्वास्थ्य विभाग में 46000, जबकि शिक्षा विभाग में 11 हजार टीचर्स की भर्तियां करेंगी। बजट में प्रदेशवासियों पर नए कर का कोई बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा। सुश्री भूरिया के अनुसार मोहन सरकार का पहला पूर्ण बजट में जन भागीदारी वाली कई योजनाएं लायी जा रही है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीब, किसान और महिलाओं पर फोकस रहेगा। इस बार जनता के हित को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, जिससे प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी।

प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री भूरिया ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि यह सर्व हारा बजट 'सबका साथ, सबका विकास' को दर्शाता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत बजट में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हेतु 18984 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आंगनवाड़ी सेवाऐं (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) हेतु रुपये

3469 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु रुपये 1231 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वही न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार केयर स्पॉनसरशिप, फॉस्टर हेतु रुपये 110 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

उन्होने बताया कि प्रदेश के इस बजट में महिलाओं, युवाओं, खिलाडियों के लिये करोडो का प्रावधान विकसित प्रदेश के लिये एक उत्कृष्ट कदम है। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है। केंद्र से 3800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि मिली है। सरकारी कर्मचारियों के भविष्य निधि भुगतान की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे रिटायरमेंट बाद तत्काल भुगतान हो सकेगा। मोहन सरकार ने अपने पहले पूर्ण बजट में जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए योजना लेकर आई है। ऐसे गरीब कैदी जो जुर्माना या अर्थदंड नहीं भर पाने के कारण जेलों में बंद हैं, उनकी रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए शुरू की जाएगी। उन्होने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट असीमित संभावनाओं को समेटकर बनाया गया है। प्रति व्यक्ति आय 11 गुना हो गई। मध्य प्रदेश में 2 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आगामी 5 वर्षों में एक्सप्रेस में नेटवर्क के माध्यम से 299 किलोमीटर का अटल प्रगति पथ, 900 किलोमीटर का नर्मदा प्रगति पथ, 676 किलोमीटर के विंध्य एक्सप्रेस-वे, 450 किलोमीटर का मालवा निर्माण विकास पथ, 330 किलोमीटर का बुंदेलखंड विकास पथ एवं 746 किलोमीटर का मध्य भारत विकास पथ के कार्य प्रस्तावित है। जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत करने पर सुश्री भूरिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री श्री जगदीश देवडा को हृदय से बधाई देते हुए विकसित मध्यप्रदेश के लिये इसे सराहनीय कदम बताया है।

संपादकीय

सत्संग संग मौत

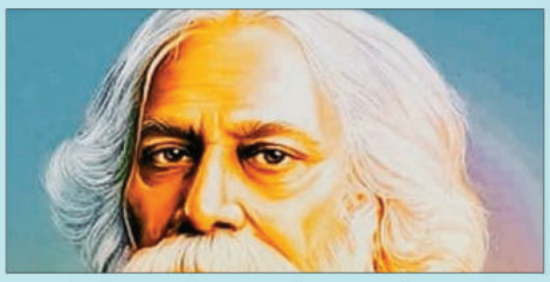

उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक सत्संग के समापन के बाद मची भगदड़ में सौ से अधिक लोगों के मरने की घटना ने पूरे देश को विचलित किया। सिकंदराराऊ के निकट फुलरई के एक खेत में कथित हरि बाबा का एक दिवसीय सत्संग चल रहा था। बताते हैं जब बाबा का काफिला जाने लगा तो सेवादारों ने करीब पचास हजार से अधिक श्रद्धालुओं को रोक दिया। गर्मी व उमस वाली भरी दोपहर में सत्संग सुनने के बाद श्रद्धालु घर जाने को बेताब थे। फिर भगदड़ मच गई और जो गिरा वो उठ न सका। लोगों की चीख-पुकार को सुनने के लिये वहां पुलिस-प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। नजदीकी जनपद एटा के अस्पतालों के बाहर लगे लाशों के अंबार हृदयविदारक थे। चारों तरफ करुण क्रंदन और अपनों को तलाशने की बेबसी थी। सौ से अधिक लाशों का ढेर देखकर आहत एक पुलिस कांस्टेबल का हार्टफेल होने से निधन हो गया। मरने वालों में अधिकांश महिलाएं थीं, वहीं कुछ पुरुष व बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को हाथरस से लगते एटा अस्पताल भेजा गया है। हादसा बड़े आयोजन में सुरक्षा उपायों की अनदेखी पर सवाल उठाता है। सवाल यह भी है कि 17 साल पहले पुलिस की नौकरी छोड़कर कथावाचक बने बाबा में ऐसा क्या सम्मोहन था कि वहां मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश व हरियाणा तक से हजारों श्रद्धालु जुटे थे। अब जांच, मुआवजे तथा कार्रवाई की बात कही जा रही है। सवाल उठता है कि इतना बड़ा आयोजन बिना पुख्ता इंतजाम के किसकी अनुमति से किया जा रहा था? क्या सुरक्षा मानकों का पालन किया गया? क्या इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा का जिम्मा पुलिस-प्रशासन का नहीं होता? जाहिर है मौतों के बढ़ते आंकड़ों के साथ ही घटना पर लीपापोती की कोशिश भी की जाती रहेगी। निस्संदेह, ऐसे बाबाओं की दुकान बिना राजनेताओं के वरदहस्त के चलनी संभव नहीं है।

बहरहाल आने वाले दिनों में जांच के बाद किसी के सिर पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ा जाएगा। मगर इन मौतों का कसूरवार कौन है? जिन लोगों ने अपनों को खोया है, उनकी कमी कैसे पूरी होगी? बताते हैं कि प्रवचन करने वाले बाबा नदारद हैं। कहा जा रहा है कि यह एक निजी कार्यक्रम था, कानून व्यवस्था के लिये प्रशासन की ड्यूटी लगाई गई थी, लेकिन आयोजन स्थल पर भीतरी व्यवस्था आयोजकों के द्वारा की जानी थी। बड़े अधिकारियों का घटना स्थल पर जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन हकीकत है कि हम पिछले हादसों से कोई सबक नहीं सीखते। हाल के दिनों में भीड़भाड़ वाले धार्मिक आयोजनों में भगदड़ में लोगों के मरने के मामले लगातार बढ़े हैं। सवाल उठना स्वाभाविक है कि भीड़ के बीच होने वाले हादसों को कैसे रोका जाए। दो साल पहले माता वैष्णो देवी परिसर में भगदड़ में बारह श्रद्धालुओं की मौत हुई थी। अप्रैल 23 में बनारस की भगदड़ में 24 लोग मरे थे। इंदौर में पिछले साल रामनवमी के दिन बावड़ी की छत गिरने से पैंतीस लोग मर गये थे। इसी तरह 2016 में केरल के कोल्लम के एक मंदिर में आग लगने से 108 लोगों की मौत हुई और दो से अधिक घायल हुए थे। पंजाब के अमृतसर में दशहरे के मौके पर रावण दहन देख रहे साठ लोगों के ट्रेन से कुचलकर मरने की घटना को नहीं भूले हैं। देश में भीड़ की भगदड़ से होने वाले 70 फीसदी हादसे धार्मिक आयोजनों के दौरान ही होते हैं। इसे रोकने को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी कुछ गाइड लाइन्स जारी की थी। जिसमें राज्य सरकार, स्थानीय अधिकारियों, प्रशासन व आयोजकों को दिशा-निर्देश दिए गए थे। जिसके लिये भीड़ प्रबंधन से जुड़े लोगों की क्षमता विकसित करने व बेहतर प्रशिक्षण का सुझाव शामिल था। प्रशासन से भीड़ के व्यवहार व मनोविज्ञान का अध्ययन कर भीड़ प्रबंधन की बेहतर तकनीक विकसित करने को कहा गया था। जिसमें तिरुपति मंदिर हेतु आईआईएम अहमदाबाद की व्यवस्था की केस स्टडी भी शामिल थी। पुलिस को भी सख्ती के बजाय अच्छे व्यवहार के लिये कहा गया था। मगर रिपोर्ट का आज भी जमीन पर असर होता नहीं दिख रहा है।

नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की चुनौती

औपनिवेशिक व्यवस्था को बदलने की बातें अरसे से होती रही हैं, पर जब बदलाव का मौका आता है, तो सवाल भी खड़े होते हैं। ऐसा ही तीन नए आपराधिक कानूनों के मामले में हो रहा है, जो गत 1 जुलाई से देशभर में लागू हो गए हैं। स्वतंत्रता के बाद से न्याय-व्यवस्था में परिवर्तन की यह सबसे बड़ी कवायद है। ये कानून नए मामलों में लागू होंगे। जो मामले भारतीय दंड संहिता के तहत पहले से चल रहे हैं, उन पर पुराने नियम ही लागू होंगे। इसलिए दो व्यवस्थाओं का कुछ समय तक चलना चुनौती से भरा काम होगा।

इस लिहाज से नए कानूनों को लागू करने से जुड़े तमाम तकनीकी-मसलों को चुस्त-दुरुस्त करने में भी चार-पांच साल लगेंगे। इसका अर्थ यह भी है कि देश में जब 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे, तब इन कानूनों की उपादेयता और निरर्थकता भी एक मुद्दा बनेगी। इस लिहाज से इन कानूनों का लागू होना बहुत बड़ा काम है। चूंकि कानून-व्यवस्था संविधान की समवर्ती सूची में आते हैं, इसलिए राजनीतिक और प्रशासनिक सवाल भी खड़े होंगे। कर्नाटक उन राज्यों में से एक है, जिसने तीन नए कानूनों का अध्ययन करने के लिए औपचारिक रूप से एक विशेषज्ञों की समिति का गठन किया है। संभव है कि कुछ मसले अदालतों में भी जाएं।

इन कानूनों की दो बातें ध्यान खींचती हैं। दावा किया गया है कि अब मुकदमों का फैसला तीन-चार साल में ही हो जाएगा। पुराने दकियानूसी कानूनों और उनके साथ जुड़ी प्रक्रियाओं की वजह से मुकदमे दसियों साल तक घिसटते रहते थे। दूसरे कुछ नए किस्म के अपराधों को इसमें शामिल किया गया है, जो समय के साथ जीवन और समाज में उभर कर आए हैं। इनमें काफी साइबर-अपराध हैं और कुछ नए सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल में उभरी प्रवृत्तियां हैं। जिस आईपीसी का स्थान भारतीय न्याय संहिता ने लिया है, वह अंग्रेज शासकों के हित में बनाई गई थी। उसका उद्देश्य न्याय से ज्यादा शासन करना था। सरकार का दावा है कि ये कानून औपनिवेशिक कानूनों की जगह पर राष्ट्रीय-दृष्टिकोण की स्थापना करेंगे, इसीलिए इनके नाम अंग्रेजी में नहीं, हिंदी में हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से पुराने कानूनों में कई बार संशोधन किए गए, पर जैसा कि गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये कानून भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाए गए हैं।

इन नए कानूनों ने तीन पुराने कानूनों का स्थान लिया है। भारतीय दंड संहिता, 1860- आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (सीआरपीसी) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (आईई एक्ट) की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) 2023 लागू किए गए हैं। देश में इस बात को लेकर काफी हद तक आमराय रही है कि पुराने कानूनों में 'भारी बदलाव' की जरूरत है। नए कानून इस 'भारी बदलाव' को व्यक्त करते हैं या नहीं, यह इस वक्त चर्चा का विषय है।

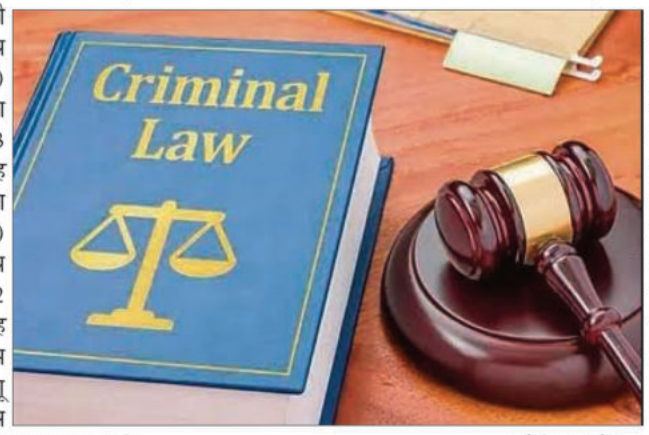

नए कानून की धारा 69 में शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना नया अपराध जोड़ा गया है। इस आरोप में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कुछ आलोचकों का कहना है कि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है और सहमति से बने रिश्तों को भी अपराध साबित किया जा सकता है। इसके जवाब में कहा जाता है कि कानून के किसी भी उपबंध का दुरुपयोग भी संभव है। सवाल सही जांच और साक्ष्यों का है, जिससे जुड़े कानून भी बदले गए हैं। इसी तरह धारा 103 के अंतर्गत नस्ल, जाति या समुदाय के नाम पर हत्या को हत्या के सामान्य अपराध से अलग श्रेणी में रखा गया है। उच्चतम न्यायालय ने 2018 में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि 'मॉब लिंचिंग' के अपराध के लिए अलग कानून बनाया जाए। अब नस्ल, जाति, समुदाय आदि के आधार पर लिंचिंग के लिए न्यूनतम सात साल की कैद या आजीवन कैद या मृत्युदंड की सजा होगी।

राजद्रोह कानून अब निरस्त हो जाएगा। वस्तुतः उच्चतम न्यायालय ने मई, 2022 में कहा था कि राजद्रोह का अपराध प्रथम दृष्ट्या अवैधानिक है और इसे समाप्त किया जाना चाहिए। नए कानून के अनुसार सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन इसमें देशद्रोह को नए अपराध के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी। महिलाओं और बच्चों को हिंसा से बचाने के लिए इसमें नए प्रावधान हैं।

कानून में आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधि के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। गैंगरेप के लिए 20 साल की कैद या आजीवन जेल की सजा होगी। पीड़िता नाबालिग है तो आजीवन कैद/मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। स्नैचिंग के मामले में गंभीर चोट लगे या स्थायी विकलांगता हो, तब कठोर सजा की व्यवस्था इसमें है। धारा 304 (1) के तहत स्नैचिंग अब नया अपराध है, जिसे चोरी से अलग किया गया है। धारा 377 को पूर्ण रूप से हटाकर समलैंगिकता, बल्कि पुरुषों और महिलाओं के बीच सहमति या गैर-सहमति से हुए अप्राकृतिक संबंधों को वैध घोषित कर दिया जाएगा। बच्चों को अपराध में शामिल करने पर कम से कम 7-10 साल की सजा होगी। चोरी, घर में नकबजनी, सेंध लगाने जैसे कम गंभीर मामलों में संक्षिप्त सुनवाई यानी समरी ट्रायल अनिवार्य कर दिया गया है। जिन मामलों में सजा तीन साल तक है, उनमें मजिस्ट्रेट लिखित में कारण दर्ज करने के बाद संक्षिप्त सुनवाई कर सकता है। सज़ा को कम करने के नियम निर्धारित- मौत की सज़ा को उम्रकैद में, उम्रकैद को सात साल, सात साल की सज़ा को तीन साल में तब्दील करना वगैरह। यह सूची बहुत लंबी है। सामुदायिक सेवा को सजा के नए तरीके के रूप में लाया गया है।

समय के साथ नई तकनीकों का इस्तेमाल भी बढ़ा है। इसके अनुरूप साक्ष्य अधिनियम में बदलाव हुए हैं। अब 'दस्तावेज' में इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर में फाइलें, स्मार्टफोन/लैपटॉप संदेश; वेबसाइट, लोकेशन डाटा; डिजिटल उपकरणों पर मेल संदेश शामिल हो गए हैं। एफ आई आर, केस डायरी, चार्ज शीट और फैसलों क ा डिजिटलीकरण जरूरी हो गया है। समन और वॉरंट जारी करना, तामील करना, शिकायतकर्ता और गवाहों की जांच, साक्ष्य की रिकॉर्डिंग, मुकदमेबाजी और सभी अपीलीय कार्यवाही, थानों और अदालतों में ईमेल के रजिस्टर, किसी भी संपत्ति की तलाशी और जब्ती अभियान की वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वगैरह-वगैरह।

प्रमोद जोशी

नए कानूनों को लागू करना आसान काम नहीं है, क्योंकि काफी समय तक पुलिस-प्रशासन और न्यायिक-प्रशासन को नए और पुराने कानूनों में अंतर करना होगा। पुराने मुकदमे चलते रहेंगे और नए आते जाएंगे। सरकार ने कानूनों को संसद में पेश करने के साथ ही इन्हें लागू करने की प्रक्रिया पर काम शुरू कर दिया था। दिसंबर, 2023 के बाद से केंद्रीय गृह सचिव ने केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ दर्जन से ज्यादा बैठकें इस सिलसिले में की हैं। वकीलों के प्रशिक्षण के साथ-साथ कानूनी शिक्षा के पाठ्यक्रम में तदनुरूप बदलाव हो रहा है। अधिकारियों की कार्यशालाएं चल रही हैं वगैरह। इस दृष्टि से यह एक बड़ी क्रांति की शुरुआत है।

विपक्ष की सकारात्मक भूमिका लोकतंत्र को बचा सकती!

डॉ. भरत मिश्र प्राची

विपक्ष की सकरात्मक भूमिका लोकतंत्र को बचा सकती! इस बार के लोकसभा चुनाव मे विपक्ष को मजबूत जनादेश मिला जिसके बल पर वह सकरात्मक कदम उठाकर लोकतंत्र को बचा सकती है। संसद में जनादेश के इस ताकत पर सरकार के गलत कदम पर ब्रेक लगाते हुये उठाकर जनहित में कदम उठाने को मजबूर कर सकती है । यह तभी संभव है जब विपक्ष मिले जनादेश की ताकत को अनर्गल बहस में न उलझाकर संसद में जनहित के मुद्दे उठाये, बहस करे, सरकार को मुद्दे पर अमल करने का दबाव बनाये। लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति अभिभाषण से शुरू होने वाला सत्र मुद्दो से भटककर टकराव की राजनीति में उलझ गया है जहां संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाजपा बनाम हिन्दू वाला बयान राजनीतिक तुल पकड़ता जा रहा है। इस बयान ने देश में एक नया राजनीतिक भूचाल खड़ा कर दिया जो लोकतंत्र हित में कदापि नहीं। इस चुनाव में देश की जनता ने विपक्ष को जो जनदेश जिस काम के लिये दिया, विपक्ष उस दिशा में कदम न बढ़ाकर गलत अपना लिया है। जो चर्चा संसद से बाहर की जा सकती उसे संसद में प्रमुख बनाकर सत्ता पक्ष को मुद्दों से भटकाने का कार्य कर रहा है। विपक्ष को जनादेश मिला है पर सत्ता पक्ष अभी भी ताकतवर है जिसने लोकसभा अध्यक्ष का चयन अपनी मर्जी के अनुसार कर विपक्ष को अपनी ताकत का अहसास करा दिया, इस बात को विपक्ष को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लोकसभा उपाध्यक्ष का चयन भी सत्ता पक्ष की मर्जी के अनुसार हीं होना है भले यह जगह अपने सहयोगी दल में से किसी को देनी पड़े पर विपक्ष को इस पद से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जब कि विपक्ष इस पद के लिये अपना उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय भी ले चुका है।

वर्तमान राजनीतिक उभरे हालात में पक्ष विपक्ष के बीच केवल आपसी अनर्गल टकराव की स्थिति उभरती नजर आ रही है, जहां वास्तविक जनहित के मुद्दे गौण हो चले है। इस तरह की स्थिति संसद में चर्चा के दौरान विपक्ष द्वारा मुद्दों से हटकर अनर्गल मुद्दे उठाने से उपजी जिसके लिये विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेवार है।

लोकसभा चुनाव में जनता ने जिसे जनादेश दिया, जिसे नहीं दिया, संसद की चर्चा का विषय नहीं है। संसद में जनहित के मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाया जाना विपक्ष का सकरात्मक कदम माना जा सकता जिससे लोकतंत्र की मर्यादा बचाने एवं सत्ता पक्ष को गलत कदम उठाने से रोकने में विपक्ष को सफलता मिलती। पर विपक्ष के उठाये वास्तविक महंगाई, बेराजगारी, नीट परीक्षा धांधली, अग्नवीर मुद्ददे को भटकाव वाला हिन्दू बनाम भाजपा का मुद्दा निगल गया। इस तथ्य को विपक्ष को समझना होगा। विपक्ष संसद में अनर्गल बहस से बचकर जनहित के मुद्दे उठाते हुये विपक्ष की भूमिका निभा सकता है जिसके लिये देश की जनता ने स्पष्ट जनदेश दिया है जो अपने सकरात्मक कदम से सत्ता पक्ष के गलत कदम को रोककर सही कदम उठाने पर मजबूर कर सकता है।

अपार संभावनाओं का क्षेत्र

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में कहा कि एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में वर्ष 2024-25 का बजट ऐतिहासिक होगा। यह देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाले विभिन्न सेक्टरों के भविष्य के दृष्टिकोण के लिहाज से बहुत ही प्रभावी दस्तावेज होगा।

नए बजट के माध्यम से सरकार पर्यटन से आय बढ़ाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की संभावनाओं को रणनीतिक रूप से आगे बढ़ाते हुए दिखाई दे सकती है। कहा जा रहा है कि भारत में घरेलू और विदेशी पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है और भारत में पर्यटन सेक्टर बढ़ने की असीम संभावनाएं हैं।

पर्यटन मंत्रालय की हालिया प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अप्रैल, 2024 के दौरान भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या 34,71,833 रही जो एक साल पहले की समान अवधि में 31,33,751 थी। इन चार महीनों में न केवल भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, वरन इन चार महीनों में पर्यटन से विदेशी मुद्रा में आय सालाना आधार पर 27.18 प्रतिशत बढ़कर 90,600 करोड़ रुपये हो गई है। ऐसे में अब पर्यटन सेक्टर को मजबूत आधार देकर पर्यटन से विदेशी मुद्रा की कमाई बढ़ाई जा सकती है। दरअसल, एक विदेशी पर्यटक से औसतन 2 लाख रुपये की कमाई होती है। साथ ही पर्यटकों का खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश का काम करता है। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से रोजगार और पर्यटन से जुड़े विभिन्न उद्योग-कारोबार भी बढ़ते हैं।

वर्ल्ड इकॉनोमिक फोरम ने यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक (टीटीडीआई) 2024 जारी किया है। 119 देशों के इस सूचकांक में भारत 39वें स्थान पर है। इसके पहले टीटीडीआई सूचकांक 2019 में भारत काफी नीचे 54वें स्थान पर था। नये टीटीडीआई सूचकांक में भारत पर्यटन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संसाधन मापदंडों पर प्रमुख पर्यटन प्रधान देशों की सूची में शामिल है। प्राकृतिक मापदंड पर भारत छठे, सांस्कृतिक, कारोबार, चिकित्सा और शिक्षा के लिए यात्रा मापदंडों पर भारत 9वें क्रम पर है। इनमें कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में भारत 18वें, हवाई यातायात की प्रतिस्पर्धात्मकता के मामले में 26वें और जमीनी एवं बंदरगाह बुनियादी ढांचे के मामले में 25वें स्थान पर है। इस पर्यटन सूचकांक के विश्लेषण से यह भी मालूम होता है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य, पर्यावरण सततता, इंटरनेट कनेक्टिविटी, और पर्यटन के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव जैसे मापदंडों पर भी भारत ने प्रगति की है।

भारत को इस बात पर ध्यान देना होगा कि दुनिया के सभी प्रमुख पर्यटन गंतव्यों देशों के पर्यटन स्थलों की प्रमुख पहचान उनकी सुंदरता और पेशेवर तरीके से तैयार किए गए उनके संग्रहालयों की भूमिका से भी है। वहां उपलब्ध बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता, साधारण से साधारण पर्यटक के लिए भी उच्च गुणवत्ता की स्थानीय सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, बसें, ट्रेन, ट्राम आदि के साथ-साथ वहां किफायती कीमत पर ठहरने और स्वच्छ व सुरक्षित आवास स्थलों की हैं।

फिलहाल, दुनिया के विदेशी पर्यटकों की कुल संख्या का कोई दो फीसदी से भी कम हिस्सा ही भारत के खाते में आ रहा है। यद्यपि पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब 6 फीसदी का योगदान करता है लेकिन इसमें सिर्फ 8 करोड़ लोगों को ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिला हुआ है।

भारत की संस्कृति, संगीत, हस्तकला, खानपान से लेकर नैसर्गिक सुंदरता हमेशा से देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती रही है। भारत एक ऐसा देश है, जिसके पास हिमालय का सबसे अधिक हिस्सा, विशाल समुद्री तट-रेखा और रेत का रेगिस्तान, कच्छ में सफेद नमक रेगिस्तान, लद्दाख में ठंडे रेगिस्तान, देश के कोने-कोने में टाइगर रिजर्व और यूनेस्को द्वारा चिन्हित धरोहर स्थलों समेत अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जैसी प्राकृतिक विविधताएं हैं। देश के विभिन्न भागों में तटीय पर्यटन, समुद्र तट पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन स्थल अपनी चिर-परिचित पहचान बनाए हुए हैं और सभी प्रकार के पर्यटकों को आकर्षित करने की अपार संभावनाएं रखते हैं। इनके अलावा रामायण सर्किट, बुद्ध सर्किट, कृष्णा सर्किट, अयोध्या में राम मंदिर, उज्जैन में महाकाल लोक और वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम जैसे आस्था केंद्रस्थल देश व दुनिया के धार्मिक पर्यटकों के कदमों को असाधारण रूप से आकर्षित कर सकते हैं।

23 मई, 2024 को प्रकाशित रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पर्यटकों ने वर्ष 2023-24 में विदेश घूमने पर 17 अरब डॉलर यानी करीब 1.41 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो कि इसके पूर्व वर्ष 2022-23 में विदेश घूमने पर किए गए व्यय की तुलना में अधिक हैं। निश्चित रूप से जहां एक ओर भारतीयों का विदेश यात्रा करने की तरफ तेजी से बढ़ता रुझान घरेलू पर्यटन के मद्देनजर नुकसान की तरह है, वहीं देश के विदेशी मुद्रा कोष को घटाने वाला भी है। इस दिशा में गंभीरता से प्रयास जरूरी हैं।

अंतरराज्यीय बाइक चोर गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार

महंगे शोक पूरे करने के लिए करते थे चोरी

माही की गूंज, मंदसौर।

बाइक चोरों की गैंग के आधा दर्जन सदस्य नई आबादी पुलिस (मंदसौर) के हत्थे चढ़े। चोरों ने मंदसौर और रतलाम जिले के अलावा राजस्थान में कई मोटर साइकिलों को निशाना बनाया। पुलिस ने आरोपियों से कुल 16 बाइक जब्त की है।आरोपी अपने महंगे मौज-शौक के लिए बाइक चोरी की घटना को अंजाम देते थे।

मंदसौर के नई आबादी थाना प्रभारी वरुण तिवारी ने बताया कि विगत कुछ समय से थाना क्षेत्र एवं आसपास लगातार मोटर साइकिल चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। 29 जून को फरियादी सोनू पिता गजानंद देवडा निवासी स्टेशन रोड नया जनता कॉलोनी मंदसौर की बाइक एमपी-14 एमजे- 7053 को सीतामऊ फाटक रामजी की होटल के सामने से अज्ञात बदमाश चोरी कर ले गए। नई आबादी पुलिस ने केस दर्ज किया। इसके बाद क्षेत्र मे कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले।

30 जून को गठित टीम द्वारा सीसीटीवी फुटेज एवं तकनीकी गुणवत्ता का प्रयोग करते हुए छ हुए आरोपीगणों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। आरोपियों की निशानदेही पर चोरी गई 16 मोटर साइकिल जब्त की गई। जिन्हें थाना क्षेत्र और आसपास के इलाकों से चोरी किया गया था। बरामद की गई मोटर साइकिलों की कुल कीमत पंद्रह लाख रुपये है। पूछताछ में पता चला कि बाइक थाना नई आबादी मंदसौर, थाना कोतवाली मंदसौर, जावरा, रतलाम, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, झालावाड़ जिले से चोरी की गई थी। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में अपने चार अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस का मानना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद और भी बाइक बरामद हो सकती है।

इनको किया गिरफ्तार

नई आबादी थाना पुलिस ने मामले में आदित्य पिता किशोर प्रजापति जाति कुम्हार उम्र 21 साल निवासी स्टेशन रोड महादेव विहार कालोनी मल्हारगढ, विक्रम पिता नाथुलाल भील उम्र 29 साल निवासी गुडबेली, थाना पिपलियामण्डी, सूरज पिता नागुलाल सुर्यवंशी जाति चमार उम्र 27 साल निवासी पलासिया थाना भावगढ, मनीष पिता दिनेश निनामा जाति भील उम्र 20 साल निवसी स्टेशन मल्टी मल्हारगढ, मांगुदास पिता रघुनाथ दास बैरागी उम्र 32 साल निवासी सेमलियारानी थाना सीतामऊ, अभिषेक सिंह पिता राजेन्द्र सिंह भदौरिया उम्र 25 साल निवासी रेलवे स्टेशन के पास मल्हारगढ को गिरफ्तार किया है।

बाइक सवार के साथ लूट की वारदात, तीन कंजर गिरफ्तार

रात में बाइक सवार के साथ हुई लूट की वारदात में पुलिस ने तीन कंजरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से लूट कर ले जाई गई बाइक के अलावा देशी कट्टा और साठ लीटर जहरीली शराब भी बरामद की गई है। आरोपियों के खिलाफ मंदसौर जिला सहित राजस्थान में एनडीपीएस, चोरी, हत्या के प्रयास जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस ने इन पर ईनाम भी घोषित कर रखा था।

भानपुरा पुलिस ने बताया कि 30 जून को भारत सिंह पिता उमराव सिंह बाइक पर सवार होकर सातली खेड़ी में खेत से गुजर रहा था। रात साढ़े ग्यारह बजे तीन अज्ञात बदमाशों ने देशी कट्टा सिर पर लगाकर डराया धमकाया। यहां उससे चार हजार रुपये, आधार कार्ड और बाइक लूटकर ले गए। पुलिस ने मामले मे केस दर्ज किया। टीम गठित कर आरोपीगणों की धरपकड़ हेतु टीमें रवाना की गई। उनि जोर सिंह डामोर की टीम मुखबिर की सुचना के आधार पर ओसारा नीमधुर रोड पर पहुंची। जहां एक मो.सा. पर तीन संग्दिध व्यक्ति आते दिखे, जिनके बाइक पर दोनों तरफ प्लास्टिक के केन लटकी हुई थी।

पुलिस को देखकर यह बाइक सवार भागने लगे। पुलिस ने पीछाकर इन्हें पकड़ा। तीनों से बिना नंबर की बाइक, देशी कट्टा मय जिंदा राउंड और साठ लीटर जहरीली शराब जब्त की। पूछताछ में इन्होंने अपना नाम राजेन उर्फ राजु कंजर पिता कालु कंजर उम्र 27 साल, नरेश पिता जसवंत कंजर उम्र 21 साल और लाधु उर्फ लाधो पिता लक्षमण कंजर उम्र 34 साल तीनों निवासी टोकडा थाना उन्हेल जिला झालावाड़ का होना बताया।

लूट वाली बाइक के संबंध में पूछताछ पर उन्होंने बताया कि घटना तीनों के द्वारा की गई थी। लूटी गई बाइक बुलेट का पेट्रोल खत्म होने से ओसारा झालावाड़ रोड पर बंद हो गई थी, जिसे सीमेन्ट फैक्ट्री में झाडियों में छुपाकर रखा गया। पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपीगणों द्वारा पूर्व में भी थाना सीतामऊ, थाना अफजलपुर, डग झालावाड (राजस्थान), उन्हेल झालावाड़ (राजस्थान) में चोरी, एनडीपीएस, हत्या का प्रयास जैसे गम्भीर अपराध घटित करना बताया है, जिनके ऊपर ईनाम भी होना स्वीकार किया गया। प्रकरण मे अग्रिम विवेचना जारी है।

लव मैरिज करने पर युवक को दी तालिबानी सजा

माही की गूंज, नीमच।

नीमच में एक युवक ने अपनी प्रेमिका से लव मैरिज कर ली। लव मैरिज से नाराज होकर लड़की के परिजनों ने मंदसौर में धोखे से बुलाकर प्रेमी और उसके दोस्त की बेरहमी से पिटाई कर दी।

युवक को बाइक पर लिटाकर जमकर पिटा। वीडियो में दिख रहा है कि युवक को बाइट पर लिटाकर कुछ लोग उसे पकड़े हुए हैं। जबकि कुछ लोग लाठी-डंडे से उसे पीट रहे हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

लड़की के मामला के घर बुलाकर युवक को पीटा

बताया जा रहा है कि, मंदसौर जिले के गांव गलियाखेड़ी में लड़की पूजा के मामा का घर है। जहां लड़के राहुल को बुलाया और उसके साथ लड़की के परिजनों ने बेहरमी से पिटाई कर दी। राहुल पास के गांव बरुचखेड़ा और पूजा नीमच की रहने वाली हैं। दोनों में प्यार हुआ और दोनों ने 7 दिन पहले ही भागकर आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। पूजा के घर वाले इस लव मैरिज से नाराज थे।

लड़की अपने मामा के यहां मंदसौर के गलियाखेड़ी गांव में 2-3 दिन पहले ही आई थी। जिसका फायदा उठाकर प्रेमी राहुल को धोखे से बुलाया गया। लड़की के परिजनों ने लव मैरिज का गुस्सा लड़के के साथ मारपीट करके निकाल दिया। मारपीट के बाद लड़के को धमकी दी कि जान से मार देंगे।

डर के नाते युवक ने थाने में नहीं की शिकायत

इसके डर से युवक बुरी तरह घायल होने बाद भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाया। तकलीफ ज्यादा होने पर आज नीमच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डर के कारण प्रेमी ने थाने में रिपोर्ट तक नहीं करवाई। घायल होने बाद भी युवक घर पर उपचार करवा रहा था। आज युवक की हालत खराब होने पर नीमच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इस मामले वीडियो वायरल होने के बाद मंदसौर के वाय डी नगर थाना की पुलिस ने 4-5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।

तेज रफ्तार कार ने चार लोगों को कुचला, दो की मौत

माही की गूंज, मंदसौर।

मंदसौर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। हादसे में एक महिला व एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल जो गई, जिनका इलाज निजी चिकित्सालय में जारी है।

मृतक व घायल राजस्थान के होरी हनुमान जी से दर्शन कर पैदल ही लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने इनको कुचल दिया। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी कार चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

मंदसौर के भावगढ़ थाना क्षेत्र में नांदवेल होरी हनुमान रोड पर सड़क किनारे खड़े दर्शनार्थियों को तेज रफ्तार कार क्रमांक जीजे 16 बिजी 7770 के चालक ने लापरवाही पूर्वक कार चलाते हुए रौंद दिया। इस हादसे में शंकरलाल पिता मांगीलाल पाटीदार निवासी मावता और अनीता बाई पति परमानंद पाटीदार निवासी मावता की मौके पर मौत हो गई। वहीं, भावना और प्रेम बाई दोनों निवासी मावता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से परिजन दोनों घायल महिलाओं को शहर के निजी अस्पताल में इलाज हेतु ले गए, जहां दोनों का इलाज जारी है।

भावगढ़ थाने में पदस्थ एएसआई हीरालाल अटोलिया ने बताया कि, घटना नांदवेल होरी हनुमान रोड़ की है। होरी हनुमान जी से पैदल दर्शन कर लौट रहे दो श्रद्धालुओं को रास्ते में बाइक सवार रिश्तेदार मिल गए थे। सभी सड़क किनारे खड़े होकर बात कर रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार कार के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला व एक पुरुष की मौत हो गई। वहीं, दो महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनका इलाज जारी है। मृतकों का पोस्टमॉर्टम जिला अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने कार जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

पशुपालन एवं जैविक खाद निर्माण प्रशिक्षण सम्पन्न

माही की गूंज, शाजापुर।

आरसेटी ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान शाजापुर द्वारा एन.आर.एल.एम. के सहयोग से ग्राम मगरोला विकासखंड शुजालपुर में आयोजित 10 दिवसीय पशुपालन एवं जैविक खाद निर्माण प्रशिक्षण का गत दिवस समापन हुआ।अनुसार प्रशिक्षण में ग्रामीण क्षेत्र की 30 स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने प्रतिभाग कर पशुओं की बीमारियों एवं उनको पालने के लिए क्या-क्या सावधानियां व ध्यान रखे जाना, जेविक खाद बनाए जाना आदि सीखा।

इस अवसर पर एलडीएम विनोद कुशवाह, मध्य प्रदेश डे. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन जिला प्रबंधक ÷कौशल÷ बलवंत शितोले, आरसेटी निदेशक मुकेश गहलोत, असेसर पी.एन. उपाध्याय, संकाय सदस्य जितेंद्र कुमार विश्वकर्मा सहित समस्त आरसेटी स्टाफ एवं समस्त प्रशिक्षणार्थी गण उपस्थित थे।

मानसून को देखते हुए रेल प्रशासन हुआ सक्रिय

माही की गूंज, रतलाम।

पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने मानसून से पहले की विभिन्न तैयारियों के लिए मिशन मोड पर काम शुरू किया है, साथ ही मैकेनिकल, सिग्नलिंग, इलेक्ट्रिकल संपत्तियों और उपकरणों आदि का उचित रख-रखाव भी किया जा रहा है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल ने सुनिश्चित किया है कि सभी कार्य निर्धारित लक्ष्य के भीतर पूरे कर लिए गए हैं। इससे आगामी मानसून के दौरान सुचारू और व्यवधान मुक्त ट्रेन सेवाएं सुनिश्चित हो सकेंगी।

आगामी मानसून के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए, विभिन्न मानसून तैयारी संबंधी कार्यों के लक्ष्यों का सावधानीपूर्वक पालन किया गया और पश्चिम रेलवे ने इन कार्यों को समय से पहले पूरा कर लिया है। पुलियों, नालों और ड्रेनों की सफाई और गाद निकालना, पटरियों के किनारे की गंदगी और कचरा साफ करना, अतिरिक्त जलमार्गों का निर्माण, उच्च शक्ति वाले पंपों की स्थापना, पेड़ों की छंटाई आदि जैसे कार्य मिशन मोड पर पूरे किए गए हैं।

बाढ़ के प्रति अत्यंत संवेदनशी सभी अंडरपासों की सुरक्षा की जांच की गई और पानी निकालने के लिए पंपिंग की पर्याप्त व्यवस्था की गई है तथा इस प्रकार के सभी अंडरपासों के पास लाइटिंग एवं मोबाइल संचार की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

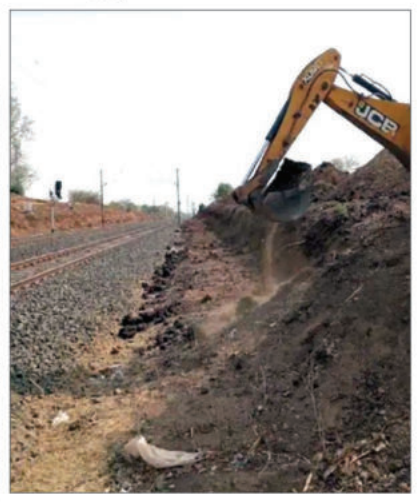

मानसून रिजर्व(बोल्डर्स, क्रेरी डस्ट आदि) आवश्यक मात्रा में वेगनों में भरकर निर्धारित स्थान पर रखे गये हैं। मंडल के सभी संवेदनशील स्थानों की पहचान कर ली गई है और ट्रैक एवं ट्रेन परिचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वहां चौकीदारों को तैनात कर दिया गया है। मानसून के दौरान ट्रेनों की सुरक्षा के लिए संवेदनशील खंडों की पहचान कर वहाँ नियमित पेट्रोलिंग की योजना बनाई गई है साथ ही संवेदनशील खंडों और स्थानों की पहचान कर रात्रि पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी की गई है।

रात्रि पेट्रोलिंग के लिए उपभोग्य सामग्रियों सहित सभी आवश्यक उपकरण तैयार रखे गए हैं। मानसून रिजर्व सामग्री जैसे बोल्डर, रेत/खदान की धूल/कोयला राख आदि पर्याप्त मात्रा में उपलबध रखे गये हैं तथा नामित स्थानों पर पर्याप्त रिलीविंग गर्डर, सीसी क्रिब आदि को एकत्रित किया गया है। किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए टेंपररी गर्डर लोड स्थिति में रेडी रखे गये हैं। रेलवे लाइन के दोनों ओर कटिंग का निरीक्षण किया गया है तथा कटिंग से गिरने वाले संभावित ढीले पत्थरों को हटा दिया गया है। सभी जल निकासी नालियों, कटिंग और यार्ड नालियों को साफ कर उसमें से कीचड़ साफकर दी गई है। मौसम संबंधी चेतावनियों जैसे उच्च गति की हवाओं, चक्रवातों, भारी वर्षा आदि की समय से सूचना प्राप्त करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय स्थापित किया गया।

इसके साथ ही रतलाम मंडल के सभी 19 एसएसई/पीडब्ल्यू कार्यालय परिसर में व्यक्तिगत सुरक्षा और मानसून सावधानी पर सुरक्षा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां व्यक्तिगत सुरक्षा, ट्रैक सुरक्षा, कर्मचारियों के कर्तव्य और जिम्मेदारियां, मानसून और इसके निवारक उपाय, मानसून पेट्रोलिंग जैसे विभिन्न विषयों पर व्यापक रूप से चर्चा की गई।

14 वर्ष पहले दूसरी जाति की लड़की से की थी लव मैरिज, अब समाज ने किया बहिष्कार

माही की गूंज, रतलाम।

अंतरजातीय प्रेम विवाह कर चुके दंपती को विवाह के 14 साल बाद अब सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते वे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। पीड़ित दंपती ने पुलिस में शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है।

महिला चंदा ने कलेक्टर और एसपी के नाम की गई शिकायत में बताया कि वह राजपूत समाज से हैं और उनका विवाह अनुसूचित जाति वर्ग के बरगुंडा समाज के महेश वर्मा से करीब 14 साल पहले हुआ था। विवाह दोनों परिवारों की सहमति से हुआ था।

समाज ने लगाया आर्थिक दंड

शादी के 14 साल बाद अब बरगुंडा समाज सकल पंच द्वारा उनके पति व परिवार पर 21 हजार रुपये का अर्थदंड कर दिया और समाज के लोगों को सूचित किया कि कोई भी हमारे घर में शादी, गमी या अन्य किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है।

इस फरमान के बाद उनका समाज में आना-जाना ही मुश्किल हो गया है। इन पाबंदियों से समाज के लोग हमें हीन भावना से देखते हैं। सामाजिक बहिष्कार की जानकारी प्रसारित भी की गई है। इससे पूरा परिवार परेशान है।

इधर सरकार अंतरजातीय विवाह को दे रही प्रोत्साहन

बता दें कि, चंदा वर्मा को शासन स्तर से अस्पृश्यता निवारण के लिए अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में भी सम्मानित किया जा चुका है। रतलाम शहर में मंगलवार को पीड़ित दंपती ने एसपी राहुल लोढ़ा को भी दोबारा आवेदन दिया है। एसपी ने कार्रवाई के लिए संबंधित थाने पर आवेदन भेजा दिया है।

आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर आधी रात को किया थाने का घेराव

माही की गूंज, रतलाम।

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर मुस्लिम समाज के लोग रोष फैल गया। पोस्ट करने वाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने रविवार रात स्टेशन रोड थाने का घेराव कर दिया। पुलिस अधिकारी कार्रवाई करने की आश्वासन दे रहे थे, लेकिन समाज के युवा आरोपित को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग पर अड़ गए। इससे वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। रविवार रात विवेक सिंह नामक व्यक्ति की आईडी से आपत्तिजनक पोस्ट करने की खबर तेजी से फैली। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच गए थे।

पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस

पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। इसी बीच लोग आरोपित की गिरफ्तारी की मांग करने लगे और भीड़ बढ़ने लगी। सीएसपी अभिनव वारंगे, स्टेशन रोड टीआई दिनेश भोजक व अन्य पुलिस अधिकारी लोगों को समझाइश देने लगे कि एफआईआर कर ली गई है।

शीघ्र ही साइबर सेल की मदद से आरोपित का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सड़क पर जाम ना लगे इसके लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दीनदयाल नगर तहना प्रभारी रवींद्र डंडोतिया, आइए थाना प्रभारी राजेन्द्र वर्मा, माणकचौक थाना प्रभारी रणजीत सिंगार आदि भी पहुंचे। थाने के सामने सड़क पर भीड़ जमा होने से जाम की स्थिति बन गई। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए भीड़ को हटाने का प्रयास किया गया। काजी आसिफ अली भी थाने पर पहुंचे तथा पुलिस अधिकारियों व लोगों से चर्चा की। उधर, दो बत्ती चौपाटी क्षेत्र में खाने की दुकाने बंद हो गईं। पुलिस ने लोगों को समझाकर घर भेजा।

कुछ देर बाद भीड़ फिर थाने पर पहुंची

रात करीब सवा बारह बजे ड़ी संख्या में लोग काजी अहमद अली को लेकर थाने पहुंचे। उन्होंने मामले को लेकर पुलिस अधिकारियों से बात की। काजी एहमद अली ने थाने से बाहर आकर समाज के युवाओं को बताया कि एफआईआर हो चुकी है।

पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कुछ लोग आरोपित को गिरफ्तार कर लाने की मांग करने लगे। उनका कहना था जब तक आरोपित गिरफ्तार नहीं होगा, तब तक वे घर नहीं जाएंगे। पुलिस व समाजजनों ने जैसे-तैसे भीड़ को समझाकर रवाना किया।

शा. हाईस्कूल में आयोजित हुआ विधिक जागरूकता शिविर

माही की गूंज, खंडवा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के अध्यक्ष व प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता जैन के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा के सचिव जिला न्यायाधीश यशवंत मालवीय के समन्वय व जिला विधिक सहायता अधिकारी कु. अनुपमा मुजाल्दे की उपस्थिति में बाल संवर्धन व संरक्षण अभियान के तहत बुधवार को शासकीय हाईस्कूल ग्राम पांजरिया में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही पंच-ज योजना के अधीन वृहद वृक्षारोपण अभियान के तहत ग्राम पांजरिया के दूरस्थ क्षेत्र में 700 पौधे व नवजीवन चिल्ड्रन होम्स खण्डवा में 20 पौधे रोपित कर उनके संरक्षण व सुरक्षा का संकल्प लिया गया।

इस अवसर पर कु. अनुपमा मुजाल्दे द्वारा बच्चों से कहा कि शिक्षा एक ऐसी सम्पत्ति है जिसका क्षय कभी नहीं होता है। इसी के साथ उनके द्वारा बच्चों को नालसा की योजना, बालकों के अधिकार, विधिक सेवा योजना व पर्यावरण संरक्षण हेतु पौधारोपण का महत्व आदि की जानकारी दी गई।

एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हुआ शुभारंभ

माही की गूंज, खंडवा।

श्री दादाजी धूनीवाले जिला चिकित्सालय खंडवा में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. संजीव कुमार दीक्षित द्वारा नीम का पेड़ लगाकर किया गया। इसके बाद सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अलग-अलग प्रकार के पेड़ लगाए गए। आर.एम.ओ. डॉ. एम.एल. कलमे, डॉ. लक्ष्मी डुडवे स्त्री रोग विशेषज्ञ, मेडिकल अधीक्षक डॉ. रंजीत बडोले, सहायक अधीक्षक संतोष मोखले, अस्पताल मैनेजर यशवंत सोलंकी सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पेड़ लगाए गए।

प्रभारी सिविल सर्जन डॉ. दीक्षित द्वारा बताया गया कि ''एक पेड़ माँ के नाम'' एक नई प्रेरणादायक पहल है। इसका उद्देश्य मातृत्व के सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत लोग अपनी माता के नाम पर एक पेड़ लगाते हैं, जो न केवल पर्यावरण के लिए लाभकारी होता है, बल्कि माता के प्रति प्रेम प्रकट करने का भी एक सुंदर तरीका हैं।

नारे लेखन कर परिवार नियोजन का दिया संदेश

माही की गूंज, खंडवा।

विश्व जनसंख्या दिवस अभियान के तहत जिले में परिवार नियोजन की जागरुकता के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाई जा रही है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. रश्मि कौशल ने बताया कि, शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में आशा एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के तहत नारे लेखन के माध्यम से छोटा परिवार का संदेश देते हुए घर-घर योग्य दंपत्तियों से भी संपर्क कर परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों की जानकारी देकर उन्हे प्रेरित किया जा रहा है। परिवार नियोजन में पुरुषों की सहभागिता भी हो उन्होंने गर्भ निरोधक अंतरा इंजेक्शन बच्चों में अंतराल का सरल साधन है। परिवार नियोजन में

समुदाय की सामाजिक भागीदारी हो, इसके लिए बच्चों में अन्तर रखने के लिए गर्भनिरोधक अन्तरा इंजेक्शन तीन माह के अंतराल में महिला को लगाकर बच्चों में अन्तर रखा जा सकता है। यह अस्थाई साधन की सेवायें जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर निःशुल्क उपलब्ध है।

3 व्यक्ति को किया जिला बदर

माही की गूंज, बड़वानी।

जिला दण्डाधिकारी बड़वानी डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस रिपोर्ट के आधार पर 1 व्यक्ति को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर किया है। जिला बदर की अवधि में यह व्यक्ति राजस्व सीमा बड़वानी एवं उसके समीपवर्ती जिले धार, झाबुआ, अलिराजपुर, खरगोन, खण्डवा, बुरहानपुर, की राजस्व सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे । जिला कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार जिला दण्डाधिकारी ने ग्राम मोहाला निवासी जतन पिता रूमसिंग मोरे को 03 माह के लिए जिला बदर किया है। एवं निवासी भावसार मोहल्ला अंजड़ निवासी निलेश उर्फ नीलू पिता मोहन सोनी को 03 माह क लिए जिला बदर किया जाता है। इसी प्रकार निवासी जहांगीर लाज के पीछे सेंधवा जतिन उर्फ गोलू पिता गौतम रावल को 04 माह के लिय जिला बदर किया जाता हैं।

अवैध खनन पर की गई कार्यवाही

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग के निर्देशन में ठीकरी क्षेत्र में अवैध खनिज परिवहन की आकस्मिक जाँच खनिज विभाग बड़वानी के द्वारा की गई। जिसमें जाँच के समय 1 ट्रेक्टर ट्रॉली मुरूम का अवैध परिवहन करते पाये जाने पर जप्त कर उचित कार्यवाही कर ठीकरी थाने की सुरक्षा में खड़ा किया गया।

संपूर्णता अभियान का हुआ शुभारंभ

माही की गूंज, धार।

भारत सरकार नीति आयोग एवं मध्य प्रदेश शासन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम अंतर्गत तीन माह का संपूर्णता अभियान कार्यक्रम दिनांक एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक चलाया जा रहा है। इस अवधि में आकांक्षी विकासखंड तिरला में दिनांक 4 जुलाई से 6 जुलाई 2024 के मध्य विकासखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जायेंगे। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तिरला जिम्मी बाहेती ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 4 जुलाई को दोपहर 1 बजे जनपद पंचायत तिरला स्थित सामुदायिक भवन में जनप्रतिनिधिगणो एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों, कर्मचारियों सहित विकासखंड तिरला के समस्त विभागों के अधिकारी, कर्मचारी एवं आम नागरिकों की उपस्थिति में होगा। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से भारत सरकार नीति आयोग का दल भी शामिल होगा। कार्यक्रम में जिसमें समस्त विभागों के अंतर्गत चल रही योजनाओं द्वारा पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित करने हेतु जानकारी साझा करने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई जावेगी साथ ही विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम अंतर्गत विकासखंड के समस्त विभागों को नीति आयोग द्वारा चयनित संकेतकों के आधार पर आगामी तीन माह में समस्त पात्र हितग्राहियों को योजना से जोड़ने का लक्ष्य प्रदाय किया गया है , जिसे संपूर्णता अभियान के माध्यम से पूर्ण किया जाना है ।

लोक सेवा केन्द्र झाबुआ की वित्तिय निविदाओं के खोले जाने की सूचना

माही की गूंज, झाबुआ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जितेन्द्रसिंह चौहान द्वारा लोक सेवा केन्द्र झाबुआ की वित्तिय निविदाओं के खोले जाने की सूचना जारी की गई है। राज्य लोक सेवा अभिकरण भोपाल 03 मई 2023 के पत्र के अनुक्रम में जिले में संचालित 06 लोक सेवा केन्द्रों के संचालन के लिये पीपीपी मॉडल के तहत प्रायवेट ऑपरेटरों के चयन हेतु ऑनलाईन निविदायें आमंत्रित की गई है। निविदाओं के अनुक्रम में वित्तिय निविदा खोले जाने की सूचना कार्यालयीन द्वारा तकनीकी निविदा में पात्र एवं अपात्र की सूची जारी कर वित्तिय निविदाएँ खोलने की सूचना जारी की गई।

लोक सेवा केन्द्रों की निविदाओं की वित्तिय निविदा खोलने के संबंध में कार्यवाही विवरण जिले के पाँच लोक सेवा केन्द्र (रानापुर, रामा, मेघनगर, थांदला, पेटलावाद) की वित्तिय निविदाएँ खोली जाकर संबंधित चयनित प्रथम निविदाकार को लेटर ऑफ अवार्ड एलओए जारी किया जा चुका है। लोक सेवा केन्द्र झाबुआ की वित्तिय निविदाएँ नहीं खोली जा सकी थी क्योकि एमपी ई-टेण्डर पोर्टल पर वित्तिय निविदाएँ खोलने हेतु न्यूनतम 02 समिति सदस्यों के डिजीटल हस्ताक्षर की आवश्यकता है, टेण्डर जारी करते समय सीईओ जिला पंचायत झाबुआ का स्थानान्तरण होने (वर्तमान में डिजीटल हस्ताक्षर उपलब्ध नहीं होने), लेखाधिकारी जिला पंचायत झाबुआ के डिजीटल हस्ताक्षर की वैद्यता समाप्त (टोकर डिस्ट्राय) होने तथा निर्वाचन आदर्श आचार संहिता (लोक सभा निर्वाचन-2024) लागू होने से वित्तिय निविदाएँ नहीं खोली जा सकी।

लोक सेवा केन्द्र झाबुआ की अंतिम सूची का प्रकाशन विभागीय पोर्टल सूचना एवं कार्यक्रम तथा जिले की वेबसाईट पर किया जा चुका है। लोक सेवा केन्द्र झाबुआ के अनुबंधित ऑपरेटर के चयन हेतु पात्र निविदाकारो की वित्तिय निविदा कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में खोली जायेगी। वित्तिय निविदाओं में एक से अधिक निविदाकार द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम दर समान पायी जाने की स्थिति में वित्तिय निविदाओं में पात्र निविदाकारो का चयन आरएफपी की कण्डिका 3.7.2 अनुसार लॉटरी पद्धति से 12 जुलाई 2024 को दोपहर 12 बजे कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में उपस्थित निविदाकारों के समक्ष किया जायेगा। चयन की कार्यवाही में निविदाकार स्वयं अथवा निविदाकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति ही उपस्थित रह सकते है, अधिकृत व्यक्ति को निविदाकार द्वारा जारी अधिकृता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में संबंधित व्यक्ति को निविदा की कार्यवाही में भाग लेने नहीं दिया जायेगा। वित्तिय निविदा में चयनित होने के पश्चात् किसी भी समय मूल दस्तावेज अवलोकन हेतु मंगाया जा सकता है, यदि मूल दस्तावेजों एवं ऑनलाईन दस्तावेजों में कोई भिन्नता एवं कमी पायी जाती है तो निविदा निरस्त की जा सकती है तथा चयनित एल-2 निविदाकार को मौका दिया जा सकता है। समस्त निविदाकार उक्त पोर्टल पर अवलोकन कर सूचित हो, पृथक् से कोई सूचना तामील नहीं कराई जायेगी।

2 व्यक्तियों को थाने पर उपस्थिति के दिये आदेश

माही की गूंज, बड़वानी।

कलेक्टर डॉ. राहुल फटिंग ने पुलिस अधीक्षक पुनीत गेहलोद की रिपोर्ट में जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रस्तावित 02 व्यक्तियो को संबंधित पुलिस थानो में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया है। कलेक्टर कार्यालय बड़वानी से प्राप्त जानकारी अनुसार निवासी ठीकरी मुकेश पिता मगन कोली को पुलिस थाना ठीकरी में 6 माह की अवधि के लिए थाना प्रभारी ठीकरी के समक्ष अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से माह जुलाई 20 एवं 30 तारीख को, माह अगस्त में 15 एवं 25 तारीख को, माह सितंबर में 15 एवं 30 तारीख को माह अक्टुबर में 05 एवं 25 तारीख को माह नवंबर में 10 एवं 20 तारीख को, माह दिसंबर में 01 एवं 31 तरीख को उपस्थित होकर देनी होगी। इसी प्रकार ग्राम चटली निवासी अनिल पिता चतरू प्रजापती को पुलिस थाना सेंधवा ग्रामीण में 04 माह की अवधि के लिए थाना प्रभारी सेंधवा ग्रामीण के समक्ष अपनी उपस्थित अनिवार्य रूप से माह जुलाई 15 एवं 25 तारीख को, माह अगस्त में 10 एवं 20 तारीख को, माह सितंबर में 05 एवं 15 तारीख को, माह अक्टुबर मे 10 एवं 31 तारीख को उपस्थित होकर देनी होगी।

27 जुलाई को पर्यटन क्विज प्रतियोगिता

माही की गूंज, खरगोन।

पर्यटन क्विज-2024 के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, क्विज नोडल अधिकारी नीरज अमझरे एवं जिला शिक्षा अधिकारी शैलेन्द्र कानूडे द्वारा क्विज पोस्टर का विमोचन किया गया। विदित है कि, मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड द्वारा प्रदेश के समृद्धिशाली इतिहास, परम्पराओं, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विविधताओं, कला, प्राकृतिक समृद्धि, महापुरूषों, पर्यटन महत्व की संभावनाओं आदि से छात्रों को अवगत कराने तथा पर्यटन के माध्यम से जागरूक करने के उद्देश्य से ''पर्यटन क्विज प्रतियोगिता'' का आयोजन किया जाता है।

पर्यटन क्विज के नोडल अधिकारी नीरज अमझरे ने बताया कि प्रतिवर्ष जिले के शासकीय एवं निजी हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल के छात्र बड़े उत्साह के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। इसमें प्रथम तीन विजेता टीमों को तीन दिन दो रात एवं उपविजेता तीन टीमों को दो दिन एक रात हेतु मध्यप्रदेश के किसी भी पर्यटन स्थल पर ले जाया जाता है। जिसमें आवास, भोजन एवं परिवहन की व्यवस्था पर्यटन विभाग द्वारा की जाती है।

27 जुलाई, 2024 को पंजीकृत टीमें उत्कृष्ट विद्यालय में प्रातः 10 से 12 बजे तक लिखित परीक्षा से गुजरेगी। लिखित परीक्षा में चयनित 6 टीम मल्टी क्विज राउण्ड से गुजरेगी।

पोस्टर विमोचन में महिला बाल विकास अधिकारी भारती आवास्या, सीएमएचओ डॉ. एमएस सिसौदिया, सीईओ जनपद पंचायत झिरन्या महेन्द्र श्रीवास्तव, भगवानपुरा सीईओ पवन शाह आदि उपस्थित रहे। जिला शिक्षा अधिकारी कानुड़े द्वारा समस्त निजी एवं शासकीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शालाओं को अपनी टीम का ऑनलाईन पंजीयन अंतिम तारीख 08 जुलाई, 2024 के पूर्व करने के निर्देश भी जारी किए है।

खरगोन जिले के पर्यटन स्थलों में अहिल्या किला एवं नर्मदा घाट महेश्वर, सिरवेल महादेव मंदिर, नवग्रह मंदिर खरगोन, चिड़िया भड़क, महाकालेश्वर, बलालेश्वर मंदिर ऊन बुजुर्ग, बाजीराव समाधि स्थल रावेरखेड़ी, जामगेट, भापसी कुण्ड, दाना कुंडी झरना, बिजागढ महादेव शामिल है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष ने ली अधिकारियों की बैठक

माही की गूंज, खरगोन।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अध्यक्ष अंतरसिंह आर्य ने 2 जुलाई को खरगोन प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक लेकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोहर सिंह बारिया, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, एसडीएम भास्कर गाचले, डिप्टी कलेक्टर सत्येन्द्र बैरवा, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग प्रशांत आर्य एवं अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

आयोग अध्यक्ष आर्य ने बैठक में अधिकारियों से कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। योजनाओं का लाभ सभी पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। गरीब आदिवासी लोगों की मदद करने में प्रशासन एवं अधिकारी पीछे नहीं रहना चाहिए। सभी अधिकारी जनप्रतिनिधियों के साथ समन्वय कर आदिवासी वर्ग के उत्थान के लिए बेहतर कार्य करने का प्रयास करें।

आयुर्वेद, होम्योपैथिक दवाईयों का हुआ निःशुल्क वितरण

माही की गूंज, धार। आयुष आपके द्वार आभियान'' के तहत बरसात के मौसम में लोक स्वास्थ सेवा प्रदाय की विभिन्न गतिविधियों का क्रियान्वयन आयुष विभाग द्वारा जिले में किया जा रहा है। जिला आयुष अधिकारी डॉ रमेशचंद्र मुवेल ने अभियान के सफल क्रियान्वन के लिए डॉ. चंपालाल पांचुरेकर को जिला नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। डॉ. मुवेल ने बताया कि बरसात में स्किन से लेकर पाचन तक की बीमारियां परेशान करती है। स्किन पर एलर्जी, डेंगू फीवर, मलेरिया, चिकनगुनिया फ्लू इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटाइटिस, टाइफाइड, पीलिया, जैसी बीमारी फैल सकती है। इनके रोकथाम के लिए आयुष चिकित्सक, आयुष महिला स्वास्थ कार्यकर्ता, आयुष कमाउंडर इत्यादि द्वारा आमजन को स्वास्थ, शिक्षा हेतु घर-घर जाकर प्रदान कर रहे हैं एवं आयुर्वेद, होम्योपैथिक दवाईयों का वितरण निशुल्क किया जा रहा है। इन बीमारियों के बचाव के उपाय भी विस्तार से बताए जा रहे हैं।

किसान भाई अपनी फसलों का बीमा करवाकर प्राकृतिक जोखिम से बचे

माही की गूंज, झाबुआ।

मौसम की अनिश्चितता को देखते हुए, प्राकृतिक आपदाओं कीट एवं रोगों से किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति में किसानों को बीमा आवरण एवं वित्तीय समर्थन प्राप्त हो सके, इस हेतु कृषि विभाग द्वारा किसान भाईयों से अपील की जाती है कि अधिक से अधिक संख्या में अपनी फसलों का प्राकृतिक क्षतिपूर्ति हेतु फसल बीमा की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 के पूर्व फसल बीमा करवा सकते है। जिससे फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई होकर, जोखिम से बचा जा सके। जिले के सभी किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ खरीफ मौसम में ले सकते है। यह योजना शासन द्वारा किसानों के हित में खेती किसानी उद्यम को समुचित आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है।

किसान फसल बीमा कहाँ करवायें

जो कृषक किसी भी कारण से फसल ऋण नहीं ले रहे हो वे कृषक अपनी फसल का बीमा अपने क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत बैंक/प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति/कामन सर्विस सेन्टर/ मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा से सम्पर्क कर आवश्यक प्रीमियम भुगतान उपरांत फसल बीमा करवा सकते है।

योजनान्तर्गत आच्छादित परिस्थितियां

इस योजना में ओला, पाला, तूफान, बाढ़, जल प्लावन, सूखा, कीट एवं रोग, आकाशीय बिजली आदि नुकसानी को शामिल किया गया है। कीट-व्याधी से फसल नुकसानी पर भी योजना में लाभ प्राप्त होगा। इस योजना में फसल वोने/रोपने अंकुरण नष्ट होने के पश्चात मौसम की विपरीत परिस्थितियों के कारण फसल को नुकसान होने पर किसान को बीमित राशि के 25 प्रतिशत का भुगतान किये जाने का प्रावधान है। इस योजना में आने वाले खर्च का वहन केन्द्र और राज्य दोनों के द्वारा किया जायेगा। योजना में वे सभी किसान लाभांवित हो सकेंगे जिसके पास स्वयं की खेती है या बटाई पर खेती की गई हो। योजनान्तर्गत सभी प्रकार की फसलो (रवी, खरीफ, वाणिज्यिक फसल) को शामिल किया गया है। ऋणी कृषकों का कराल ऋण प्राप्त करते समय बैंक द्वारा स्वतः फसल बीमा करवाया जा सकेंगा किसान योजना से बाहर होने का विकल्प बीमांकन की अंतिम तारीख के 07 दिवस पूर्व चुन सकता है।

योजना के तहत प्रीमियम दर

खरीफ फसलों हेतु बीमित राशि का 2 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो एवं कपास फसल के लिए 5 प्रतिशत या वास्तविक दर जो भी कम हो लागू होगी।

जिले हेतु निर्धारित ऋणमान

खरीफ फसल 2024हेतु ऋणमान प्रति हेक्ट. रुपये में निर्धारित किया गया है जिसमे धान सिंचित 30 हजार रुपये, धान असिंचित 22 हजार रुपये, मक्का 26 हजार रुपये, ज्वार 22 हजार रुपये, बाजरा 15 हजार रुपये, मूंगफली 19 हजार 500 रुपये, सोयाबीन 36 हजार रुपये, कपास 50 हजार रुपये, मूंग 22 हजार 800 रुपये, उडद 25 हजार रुपये एवं तुअर 30 हजार 800 रुपये है।

फसल बीमा हेतु कृषक श्रेणी

ऋणी एवं अऋणी किसानों का फसल बीमा समान होगा। ऋणमान का निर्धारण स्केल ऑफ फाइनेंस के आधार पर होगा। ऋणी कृषक :- ऋणी कृषकों का फसल ऋण प्राप्त करते समय बैंक द्वारा स्वतः फसल बीमा करवाया जा सकेगा। अऋणी कृषक :- जो कृषक किसी भी कारण से फसल ऋण नहीं ले रहे हो वे कृषक अपनी फसल का बीमा उनके क्षेत्र की राष्ट्रीयकृत / सहकारी /ग्रामीण बैंक शाखा/कामन सर्विस सेन्टर से सम्पर्क कर आवष्यक प्रीमियम भुगतान उपरांत फसल बीमा करवा सकते है।

अऋणी कृषक कृषको हेतु फसल बीमा करवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज

पूर्णतः भरा हुआ प्रस्ताव फार्म (बैंक एकाउण्ट की समस्त जानकारी सहित), भू-अधिकार पुस्तिका, सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया बुवाई का प्रमाण-पत्र (पटवारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा प्रदान किया जावेगा), पहचान पत्र (मतदाता पहचान पत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि) एवं बैंक पासबुक की प्रतिलिपी।

खरीफ 2024 हेतु अधिसूचित की गई फसलें

जिला स्तर पर :- उड़द फसल,

तहसील स्तर पर :- झाबुआ एवं रामा में मूंगफली एवं कपास फसल।

राणापुर में ज्वार, मूंगफली एवं कपास फसल।

मेघनगर, थांदला एवं पेटलावद में कपास फसल।

फसल बीमा के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान हेतु निकटवर्ती बैंक शाखा, प्राथमिक सहकारी साख समिति, कृषि विभाग, के मैदानी अमले, बीमा कम्पनी के प्रतिनिधी तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी कार्यालय एवं कार्यालय उप संचालक कृषि कार्यालय से सम्पर्क कर सकते हैं।

सेवानिवृत सीआरपीएफ जवान के नगर आगमन पर किया भव्य स्वागत

माही की गूंज, अलीराजपुर।

अलीराजपुर जिले के छोटे गाँव रामसिंह की चौकी के रहने वाले अन्तरसिंह कलेश केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में नियुक्त होकर देश की सीमाओं पर 20 वर्षों तक सेवा करने के बाद अपने पद से दिनांक 30 जून 2024 को सेवानिवृत्त होकर अपने गृह गाँव लोटे। जिनका आलीराजपुर नगर में दिनांक 1 जुलाई 2024 सोमवार को आगमन होने पर परिवार के सदस्यों, नगरवासियों व विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया गया है।

सर्वप्रथम स्थानीय टंट्या भील चैराहे पर उनका काफिला पहुँचा।वहाँ पर एकत्रित परिवार के सदस्यों, नगरवासियों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने फटाके फोड़कर गर्मजोशी से स्वागत किया। भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। टंट्या भील गाता पर परम्परागत एवं आदिवासी संस्कृति, रीति रिवाज अनुरूप पूजापाठ कर सेवानिवृत जवान अंतर सिंह कलेश एवं परिवार को खुली जिप्सी में बैठकर स्वागत रैली नगर के प्रमुख मार्ग रामदेव जी मंदिर, पोस्ट ऑफिस चौराहा,निम चौक, बस स्टैंड पहुँची।शहर में विभिन्न जगह पर नगर वासियों के द्वारा जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। स्वागत रैली में उनके सम्मान के लिये रैली के आगे आदिवासी सांस्कृतिक लोक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी जा रही थी। स्वागत के लिए हर चौराहे पर भीड़ एकत्रित थी, नारे लग रहे थे। आगे आगे वाद्य यंत्र ढोलकिया मांदल के साथ जुलूस बढ़ रहा था, नृत्य के साथ ही फटाके की लड़ फोड़ी जा रही थी। लोग देश भक्ति के माहौल रिमझिम बारिश से भीगते हुए चल रहे थे।

स्वागत रैली के समापन के बाद उनके निवास स्थान फतेह क्लब के सामने मंचीय एवं स्वागत सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया।वहां पर ग्राम रामसिंह की चौकी के पटेल,सरपंच एवं ग्रामवासियों के द्वारा साफा बांध कर स्वागत किया गया।आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन (आकास) के द्वारा साल श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया है।मंचासीन अथिति आकास जिला उपाध्यक्ष बहादुर सिंह रावत, लालसिंह डावर, समाज के वरिष्ठ रतन सिंह राही, जयस जिला अध्यक्ष अरविंद कनेश, एबीवीपी के विनय चौहान, पटवारी नितेश अलावा आदि ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। श्री कलेश ने भी अपने सेवाकाल के अनुभव सुनाये।स्वागत भाषण आकास जिला अध्यक्ष भंगुसिंह तोमर ने दिया। कार्यक्रम का संचालन रतनसिंह रावत अजाक्स जिला अध्यक्ष ने किया एवं सेवानिवृत जवान कलेश की धर्मपत्नि श्रीमति रमतू कलेश ने आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आकास जिला उपाध्यक्ष लालसिंह डावर, महासचिव सुरेंद्र सिंह चौहान, सचिव केरम सिंह चौहान, अन्नू चौहान, जोबट आकास तहसील अध्यक्ष पातलसिंह चौहान, जयस के पूर्व जिला अध्यक्ष विक्रमसिंह चौहान, आदिवासी छात्र संगठन (एसीएस) के जिला अध्यक्ष विकय कनेश, जागरसिंह किराड़,सुरेश तोमर, परसुराम तोमर, कालू कलेश, भारत कलेश, गुलाबी तोमर, विद्या बन्दोड, कमला मंडलोई, जोहार भिंडे, राजेन्द्र रावत, सलाम सोलंकी, वीरेन्द्र सिंह बघेल जोबट, गौतम सस्तिया सोंडवा आदि उपस्थित थे।

बारिश से पहले ही प्रशासन को दी थी सूचना अब उखड़ा मार्ग बना सिरदर्द

माही की गूंज, बरझर। फिरोज खान

बरझर से छोटोंपोल आजाद नगर (भाबरा) प्रधानमंत्री सड़क मार्ग में हालत बरसात के मौसम में खराब होते नजर आ रही हैं। साइट पट्टी से लेकर जगह-जगह सड़क मार्ग पर गड्ढे दिखाई दे रहें हैं प्रशासन को अवगत होने के बाद भी इसका सुधार बरसात के पहले नहीं किया गया। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग बरझर-छोटीपोल 9 किलोमीटर की हालत बरसात में देखते ही बनतीं है। साइट पट्टी का डामरीकरण उखड़ चूका है वहीं झाड़ियों से भी वाहन चालक परेशान हैं। सम्बन्धित अधिकारियों की अनदेखी के चलते अब सड़क किनारे रहवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है वहीं अब मवेशियों को भी सड़क मार्ग पर खुटी लगाकर बांधना प्रारम्भ कर दिया है। जबकि प्रशासनिक अधिकारियों के इस सड़क मार्ग से गुजरने के बाद भी अनदेखी कर निकल जाते हैं। साथ ही इस सड़क मार्ग पर ढेड़ दर्जन से ज्यादा गतिरोध बने हैं जो वाहन चालकों के सामने अचानक आ जाते हैं जिससे वाहन के उछलने से खासकर अस्पताल ले जाने वाले मरीजों व गर्भवती महिलाओ को काफ़ी परेशानी होती है। अब तो जिसकी मनमर्जी हो वो वहां गतिरोध बना लेता है और अधिकांश वहीं गतिरोध है। परन्तु विभागीय अधिकारियों इस सड़क मार्ग का सालों से कभी निरक्षण ही नहीं किया तो वह भी इससे वाकिफ नहीं हैं। साथ ही ग्रामीणों ने मांग है कि, आजाद नगर भाबरा जाने के लिए कम समय व कम दूरी है जिसके चलते साढ़े तीन मीटर सड़क मार्ग को साढ़े पांच मीटर सड़क बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है ताकि दो वाहन क्रास हो सके।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता संघ ने संपर्क ऐप के विरोध में कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

माही की गूंज, अलीराजपुर।

महिला बाल विकास विभाग द्वारा संपर्क ऐप चलाकर कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को उपस्थिति लगाने एवं सभी दैनिक गतिविधियों को भरने के लिए बाध्य किया जा रहा है। जबकि भारत सरकार का ऐप पोषण ट्रेकर पर उपस्थिति के साथ सभी गतिविधियों को भरा जा रहा है। तो दो-दो ऐप पर कार्य कराने का क्या उद्देश्य है। अल्प मानदेय मैं काम करने वाली हम महिला कर्मचारियों को इतना परेशान क्यों किया जा रहा है जबकि सुपरवाइजर, परियोजना अधिकारी मात्र एक ही ऐप पर कार्य कर रहे है।

संपर्क ऐप को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाये इस हेतु संपर्क ऐप के विरोध मैं एक दिवसीय आन्दोलन कर ज्ञापन दिया, जिले की छः परियोजनाओं दुवारा जिला स्तर पर दिया दिया और सभी केन्द्र पूर्णतया बंद रखे गए। इस दौरान जिला मंत्री धनसिंह कनेश, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मंजुला लोहार, जिला अध्यक्ष रेशमा बामनिया, जिला उपाध्यक्ष कमला रावत, एक कर्मठ एवं जुझारू कार्यकर्त्ता नीरा कनेश जोबट अध्यक्ष संगीता डूडवे, चंद्रशेखर आजाद नगर सरोज चौहान, सोंडवा से रंजीता कनेश, लीला निंगवाल, लुम्बाई बघेल, संतोषी, प्रीति, कला, उदयगढ़ से कलबाई मेडा,कांता मूवल, सोनू चौहान, सायरी चौहान, उषा बामनिया, कुसुम सस्तिया नेरबाई, निर्मला चौहान, सलमा वासुनिया, प्रमिला डावर, सोनल भयडिया, शर्मीला, सावित्री किराड़ वनिता, अनबाई संघ के सभी प्रतिनिधियों एवं जिले की सभी कार्यकर्ताओ उपस्थित रही।

नवीन अपराध अधिनियम 2023 के तहत आम्बुआ में प्रथम अपराध दर्ज

माही की गूंज, आम्बुआ।

अंग्रेजों के जमाने से लागू कानून को हटाकर नवीन कानून लागू किया गया है नवीन अपराध अधिनियम 2023 के तहत वर्ष 2024 की एक जुलाई से नवीन अधिनियम लागू होने के बाद अलीराजपुर जिले के आम्बुआ के पुलिस थाने पर नवीन अधिनियम के तहत प्रथम अपराध पंजीकरण हुआ है।

हमारे प्रतिनिधि को थाना प्रभारी योगेंद्र मंडलोई ने बताया कि, अब नवीन अधिनियम में बने नए कानून के तहत कार्यवाही होना है इसी कड़ी में 1 जुलाई को आम्बुआ थाने में प्रथम अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत धारा 296, 281,125 (क) 351(2) के तहत पंजीकृत किया जा कर फरियादी को प्रथम सूचना दर्ज की एक प्रति दी गई।

पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर भटकते बच्चे को उसकी मां को सौंपा

माही की गूंज, बड़नगर।

अरमान पिता नारू खान जाति मुसलमान (10) निवासी समता परिसर रतलाम का जो ट्रेन में बैठकर बड़नगर रेलवे स्टेशन उतर गया था जो भटक गया था। जिसको बड़नगर निवासी अकरम खान द्वारा थाने पर लाकर छोड़ा गया। बड़नगर पुलिस द्वारा परिजनों से संपर्क किया गया और बालक को उसकी माता हिना पति नारू खान जाति मुसलमान (30) निवासी समता परिषद रतलाम को सौंप दिया। बड़नगर पुलिस हमेशा अपने कर्तव्य को लेकर जन कल्याण की भावना को लेकर हमेशा अपना फर्ज अदा करती हैं। पूरे उज्जैन जिले में बड़नगर थाने की पुलिस हमेशा सतर्क रहने वाली और अपराधों पर सख्त कार्रवाई करने के नाम से जानी जाती है।

दीक्षारंभ कार्यक्रम का हुआ शुभारंभ

माही की गूंज, चं.शे. आजाद नगर।

शासकीय महाविद्यालय चंद्रशेखर आजाद नगर भाबरा में तीन दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना के पश्चात महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.एस. डोडवे ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से किया। डोडवे ने नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों हेतु इस तीन दिन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य बताने के साथ नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों को सूर्य का उदाहरण देते हुए जीवन में अनुशासन का महत्व बताया और उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी। महाविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी एवं स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयोजक प्रो. एम.एस. डोडवा ने नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों को महाविद्यालय के समस्त स्टाफ एवं विभागों के बारे में जानकारी दी साथ ही पूर्व से अध्ययनरत छात्रों से परिचय करवाया। नवीन शिक्षा नीति प्रभारी प्रो. दिलीप गरवाल द्वारा विद्यार्थियों को नवीन शिक्षा नीति के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। कार्यक्रम का संचालन प्रो. कमलेश गणावा द्वारा किया गया तथा उनके द्वारा तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम की रूपरेखा भी बतायी गयी। आभार ई-प्रवेश नोडल अधिकारी डॉ. नवनीत सांकला द्वारा व्यक्त किया गया तथा विद्यार्थियों को महाविद्यालय परिसर का भ्रमण करवाया गया। इस कार्यक्रम में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ पूर्व से अध्ययनरत छात्र एवं समस्त महाविद्यालयीन स्टॉफ उपस्थित रहें।

10 करोड़ से अधिक की लागत से महाराजवाड़ा बनेगा हेरिटेज होटल

माही की गूंज, उज्जैन। विजय सोलंकी

उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन के समीप स्थित महाराजवाडा को 10 करोड़ से अधिक की लागत से हेरिटेज होटल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने महाराजवाड़ा पहुंचकर निर्माण कार्यों का बारीकी से अवलोकन किया और निर्माण एजेंसी एमपी टूरिज्म और संबंधित ठेकेदार को तेजी से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उल्लेखनीय है कि, सिहंस्थ 2028 के तैयारियों के क्रम में महाराजवाडा को हेरिटेज होटल बनाया जा रहा है। जिसमें 21 से अधिक रूम, रूफटॉप रिस्टोरेंट आदि कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। कलेक्टर सिंह ने एमपी टूरिज्म के अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यों को गुणवत्तापूर्ण रूप से समय पर पूरा कराएं। इसके बाद कलेक्टर सिंह ने लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

नवागत चौकी प्रभारी ने ली ग्राम सुरक्षा समिति की बैठक

माही की गूंज, बरझर।

बढ़ती चोरी की वारदातो को रोकने व आगामी त्योहारी को शांत पूर्वक मनानें को लेकर नवागत चोकी प्रभारी एमएस हाडा ने ग्राम पंचायत भवन बरझर में ग्राम सुरक्षा समिति सदस्य ओर ग्रामवासियों की बैठक ली। बैठक में नवागत चोकी प्रभारी हाडा ने ग्राम में बढ़ती चोरी की वारदातो को रोकने को लेकर ग्राम वासियों से बात की। उन्होंने कहा कि, रात्रि में अपने अपने घरों के मकान के आगे और पिछे लाइट जलाकर रखें व सरपंच हिमसिग बारिया से स्टेट लाइट खंबों पर बंद है उसे चालू करवाए। जिससे गस्त में रात्रि में परेशानी ना हों और पुलिस को सहयोग करने की बात ग्रामीणों से कही। चर्चा के दोरान चोकी प्रभारी ने कहा, रात्रि गस्त में पुलिस के द्वारा ग्राम में चार जगाह पॉइंट लगाएं है निम चोक, पांचाल मोहल्ला, हनुमान मंदिर चौराहा, महिंद्रा रोड पर पुलिस के पाइंट रहेंगे। वहीं रात्रि में दो व चार पहिया वाहनों को रोक कर तलाशी ली जाएगी। चोकी प्रभारी ने कहा, पुलिस के पास पर्याप्त बल नहीं होने के चलते रात्रि गस्त में गांव वासी पुलिस को सहयोग करे। जिससे वारदातो को रोका जा सके इस पर ग्रामवासियों ने भी पुलिस को सहयोग करने की बात कही व हर पांइट पर पुलिस के साथ रात्रि गस्त करने को कहा जिससे ग्राम में सुरक्षा बनी रहै। बैठक में आगामी मोहर्रम के त्योहार में भाईचारा से मनाने को लेकर कहा। अभी तक बरझर शांतप्रिय कस्बा है। सभी समाजन त्यौहार को भाईचारे से मनाते आ रहे हैं। गाम सरपंच हिमसिग बारीया ने भी पुलिस को पुरा सहयोग करने की बात कही। बिजली के खंबों पर जहां बंद है स्टैंड लाइट चालू करने को कहा साथ ही रात्रि में पुलिस को सहयोग बनाएं रखने कि बात कही। बैठक में इरसाद खान ने भी चौंकी प्रभारी व सरपंच के समक्ष अपनी बात रखी।

बैठक में चोकी प्रभारी हाडा, एएसआई संतोष राजपुत, सरपंच हिमसिह बारिया, पंच ईरसाद खान, मागीलाल प्रजापत, हातिम बोहरा, गोरधन राठोर, धना प्रजापत, कांतिलाल, सुरेश पांचाल, कुतबी हुसैन, एजाज खान, सोहन लाल साहू, योगेस साहू, पवन शाहू, मिलन पंचाल, शान्तीलाला प्रजापत, चोकीदार व बड़ी संख्या में ग्राम वासी उपस्थित रहे।

लंबे इंतजार के बाद रूनीजा में 2 करोड़ 95 लाख की लागत से बनने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्य हुआ प्रारंभा

साढ़े चार बीघा में बनेगा 6 बिस्तर का सर्व सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र

माही की गूंज, बड़नगर/रुनीजा।

रुनीजा तथा क्षेत्र वासियो को बड़े लंबे अंतराल के बाद लगभग 1 वर्ष बाद 6 बिस्तर के उपस्वास्थ्य केंद्र की सुविधा मिलने वाली है। रुनीजा में मध्य प्रदेश शासन के द्वारा वर्ष 2023 में 6 बिस्तर के उपस्वास्थ्य केंद्र भवन की स्वीकृति प्रदान की गई थी लेकिन शासकीय भूमि के अभाव में उक्त स्वास्थ्य केंद्र एक वर्षों से अधिक समय से अधर में लटका हुआ था। आम जन लग रहा था की यह सविधा अब मिलना मुश्किल है। लेकिन अब जाकर अनुविभागीय अधिकारी शिवानी तरेटिया और तहसीलदार माला राय के द्वारा शासकीय भूमि पर सर्वे क्रमांक 230 रकबा 090 साढ़े चार बीघा जमीन उपलब्ध करवाई गई। उक्त केंद्र का कार्य प्रारम्भ होने से क्षेत्र वासियो ने प्रशन्नता व्यक्त की है।

बता दे कि, उक्त सुविधा के अभाव में रुनीजा सहित आसपास के क्षेत्र वासियों को छोटी-मोटी बीमारी के लिए या तो किसी प्राइवेट चिकित्सक किया या फिर रतलाम, बड़नगर जाकर अपना इलाज करवाने पड़ता था। अब यह सुविधा रुनीजा में उपलब्ध होने पर यहां एमबीबीएस डॉक्टर एवं स्वास्थ्य विभाग की पूरी उपलब्ध रहेगी।

इस संदर्भ जानकारी देते हुए ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. विजेंद्र अजनार ने बताया कि, यह स्वास्थ्य केंद्र वर्ष 2023 में ही स्वीकृत हो चुका था लेकिन समय पर जगह नहीं मिलने से विगत काफी समय से इसका काम अटका हुआ था। अब जाकर शासन द्वारा जगह उपलब्ध कराई गई और उसके बाद यह 2 करोड़ 95 लाख का 6 बिस्तर का उप स्वास्थ्य केंद्र लोक निर्माण विभाग के मार्ग दर्शन बन रहा है। जिसमे चिकित्सकों के वह स्टाफ के रहने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

रोटी, कपड़ा, मकान और डाटा...?

माही की गूंज, । संजय भटेवरा

पहले आदमी की तीन मूलभूत आवश्यकता थी रोटी, कपड़ा और मकान और आम आदमी इन तीनों को ही कमाने में लगा रहता था। कई लोगों का पूरा जीवन ही इन तीनों में खफ जाता था और वे इससे आगे कुछ सोच ही नहीं सकते थे। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया आदमी की आवश्यकता भी बढ़ती गई। हालाकी आवश्यकता होती है और आम इंसान को कितना भी मिल जाए उसे कम ही लगता है और इसीलिए इसे निन्यानवे का फेर कहा गया है।

आदमी जीवन भर निन्यानवे को 100 करने के चक्कर में लगा रहता है। लेकिन वर्तमान युग में तीन मूलभूत आवश्यकता में एक और आवश्यकता बढ़कर चार हो गई है रोटी, कपड़ा, मकान के साथ उसमें डाटा भी जुड़ गया है। हाल ही में दूरसंचार कंपनियों ने अपने कॉलिंग और डाटा टैरिफ में 20 से 25 प्रतिशत की वृद्धि करके आम इंसान की रोजमर्रा जिंदगी पर तगड़ा प्रहार किया है। क्योंकि आज मोबाइल फोन आम इंसान की जिंदगी की जरूरत का महत्वपूर्ण साधन बन गया है लेकिन दूरसंचार कंपनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है।

ये निजी कंपनियां अपने मन माफिक टेरिफ बनाकर डाटा के नाम पर कॉलिंग के पैसे में भी बेहताशा वृद्धि कर आम आदमी की जेब पर सीधा प्रहार कर रही है।

चुनाव के पश्चात ही निर्णय क्यों..?

दूरसंचार कंपनियों द्वारा दाम बढ़ाने के निर्णय के टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें तत्काल पश्चात इस प्रकार इतने अधिक रेट बढ़ना आम नागरिकों को आक्रोशित कर रहा है। सोशल मीडिया पर तरह-तरह के मिम्स के माध्यम से उपभोक्ता अपना दर्द बयां कर रहा है। कोई इसे सरकार द्वारा दूरसंचार कंपनियों को आम आदमी को लूटने की खुली छूट बता रहा है, आम लोगों का कहना है कि, सरकार निजी उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकारी कंपनी बंद कर निजी कंपनियों को बढ़ावा देकर नीजीकरण के माध्यम से जनता को लूटने में लगी है।

एक तरफ देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, उसी देश में दूरसंचार कंपनियां प्रति उपभोक्ताओं से लगभग 300 रुपये महीने डाटा के नाम पर वसूली कर रही है। आज के युग में मोबाइल के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है ऐसे में 80 करोड लोग जो सरकारी मुफ्त राशन पर अपना गुजर बसर कर रहे हैं उनके लिए 300 रुपये महीने का रिचार्ज करवाना भारी भरकम नजर आ रहा है। वहीं अगर परिवार में दो या तीन सदस्य के पास मोबाइल है तो यह खर्च और भारी पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि, मोबाइल कंपनियां 4जी और 5जी के नाम पर खुली लूट मचाने में लगी है ऐसे में उन पर शासकीय नियंत्रण आवश्यक है। यही नहीं सरकार को चाहिए कि वो डाटा और कॉलिंग टैरिफ को अलग-अलग कर अपना टैरिफ प्लान जारी करें जिससे अगर व्यक्ति डाटा का उपयोग नहीं करना चाहता तो वो केवल कॉलिंग टैरिफ लेकर केवल बात करने के लिए मोबाइल का उपयोग कर सके। पहले इन निजी कंपनियों ने कम दर और फ्री में डाटा देकर आम लोगों को इसका आदी बना दिया और अब मनमाने तरीके से अपने प्लान के रेट बढ़ा रहे हैं।

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने थांदला शहर की तीन उचित मूल्य दुकानों का किया निरीक्षण

अनियमित्ता पर कारण बताओ सूचना पत्र जारी

माही की गूंज, झाबुआ।

कलेक्टर नेहा मीना के आदेशानुसार एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व थांदला तरुण जैन ने थांदला शहर की तीन उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया। उपभोक्ता भंडार द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान शहरी क्रमांक 2 और शहरी 03 में व्यवस्थाएं एवं वितरण ई केवाईसी का कार्य संतोषप्रद पाया तो वहीं विपणन सहकारी संस्था थांदला द्वारा संचालित शहरी क्रमांक 3 पर ई केवाईसी कम होने एवं दुकान पर स्टॉक में अत्यधिक अंतर होने से विक्रेता जगदीश वर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान छोटा जुलवानिया, बड़ा जुलवानीया, पलाशडोर, पांचखेरिया, काकनवानी का निरीक्षण भी किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के काकनवानी दुकान पर स्टॉक अंतर होने से विक्रेता जय नारायण शाक्य को कारण बताओ सूचना पत्र जारी की जा रहा है। एसडीएम ने दुकान पर आवश्यक साफ-सफाई एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण करने की सख्त हिदायत संचालनकर्ता समिति के प्रबंधक एवं सेल्समैनों को दी है।

बंद हुआ पिटोल आरटीओ चेक पोस्ट, बिना रोकटोक होगा आवागमन

सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पर अवैध वसूली की शिकायतों पर हुआ बदलाव

माही की गूंज, झाबुआ।

मध्यप्रदेश -गुजरात की सीमा पर बने पिटोल चेक पोस्ट पर रविवार तक जहां वाहनों का जमघट लग रहा था, वहीं अब सोमवार से इस पर सन्नाटा पसरा पड़ा है। ऐसा नहीं है कि वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। आवागमन तो सामान्य दिनों की तरह ही चालू है लेकिन चेक पोस्ट पर अब रोकटोक बंद हो चुकी है और वाहन सरपट दौड़ते यहां से निकल रहे है। हालांकि चेक पोस्ट परिसर की सुरक्षा को देखते हुए यहां कुछ जवानों की तैनाती की गई है।

दरअसल शासन ने 1 जलाई से प्रदेश के सभी चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए थे। इसके बाद से ही पिटोल स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट से भी सारे बैरियर और कर्मचारियों को हटा दिया गया है। इस स्थिति के बाद से ही मध्यप्रदेश से गुजरात और गुजरात से मध्यप्रदेश में आने -जाने वाले सारे वाहन बिना किसी रोकटोक के गुजर रहे है। अब वाहन चालकों को चेकपोस्ट से गुजरने के लिए घंटों इंतजार नहीं करना पड़ रहा है।

पिटोल स्थित इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट से हर दिन हजारों वाहन निकलते है। इन वाहनों से शासन को राजस्व के रूप में प्रति माह लगभग एक करोड़ रूपये का राजस्व मिलता रहा है। यह राजस्व टैक्स और दंड के रूप में वसूला जाता रहा है। इस हिसाब से इस इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट का सालाना राजस्व वसूली का आंकड़ा लगभग 12 करोड़ के आसपास पहुंच जाता था। चेक पोस्ट बंद होने के बाद अब शासन को मिलने वाले राजस्व में एक बड़ा झटका भी लग सकता है।

हालांकि चेकपोस्ट बंद होने से कई धंधेबाजों को इसका नुकसान हुआ है तो वहीं कई माफियाओं को इससे सीधे तौर पर लाभ मिलता नजर आ रहा है। चेकपोस्ट बंद होने से कई धंधेबाजों और चटरगुल्ले नेताओं को तगड़ा झटका लगा है। ये धंधेबाज जोड़-जुगाड़ कर ओव्हर लोड और अवैध ट्रकों को चेक पोस्ट से पार करवाते थे। जिसके बदले वाहन मालिकों से निर्धारित राशि वसूली जाती थी। इस धंधे में क्षेत्र के कई लोग शामिल थे जो पिटोल चेकपोस्ट पर कुकुरमुत्तों की तरह नजर आते थे। लेकिन चेकपोस्ट बंद होने से इनकी दुकानदारी का सुपड़ा साफ हो गया है।

इसके अलावा चेकपोस्ट बंद होने का सीधा फायदा भी बड़े अवैध धंधेबाजों को होता दिखाई दे रहा है। चूंकि यह चेकपोस्ट मध्यप्रदेश-गुजरात की सीमा पर है तो अवैध धंधेबाज के लिए यह चेकपोस्ट पहले सरदर्द बना हुआ था। अवैध धंधेबाज और माफिया इस चेक पोस्ट से ना गुजर कर बार्डर पर बसे छोटे गांवों से प्रधानमंत्री सड़क का सहारा लेते हुए अपने अवैध धंधे करते थे, लेकिन अब पिटोल स्थित इंटिग्रेटेड चेकपोस्ट बंद हो चुका है। इसका सीधा फायदा माफियाओं को मिलेगा। क्योंकि अब बिना किसी रोकटोक के मुख्य मार्ग से ही ये माफिया अपना अवैध धंधा अंजाम दे सकेंगे।

गौरतलब हो की पष्चिमी मध्यप्रदेश के छोर पर बसे आदिवासी बाहुल जिले में सबसे बड़ा अवैध धंधा शराब का है और शराब माफिया लगातार शराब की अवैध तस्करी गुजरात के लिए करते रहे है। जिले की शराब दुकानों के टैंडर माफियाओं द्वारा अरबों रूपयों में लिए जाते है। जबकि यह अरबों रूपये की शराब जिले में नहीं खपाई जाती अपितु पड़ोसी राज्य गुजरात में अवैध रूप से पहुंचाई जाती है। इसीलिए जिले की बर्डर पर स्थित शराब दुकानों के टैंडर करोड़ों अरबों रूपये में जाते है और शराब माफिया अवैध तरीके से करोड़ों की शराब तस्करी बार्डर क्रास कर पड़ोसी राज्य गुजरात में करते है। हालांकि पहले चेकपोस्ट चालू रहते माफिया इस रास्ते को नजर अंदाज कर ग्रामीण सड़कों से गुजरात में प्रवेश कर अवैध शराब पहुंचाते थे, लेकिन अब चूंकि पिटोल चेकपोस्ट पूरी तरह से बंद हो चुका है तो माफियाओं के लिए भी यह मुख्य मार्ग अवैध धंधों के लिए खुल चुका है। जिसके चलते शराब माफियाओं के साथ ही अन्य अवैध धंधेबाजों और माफियाओं के भी वारे-न्यारे होते दिखाई दे रहे है।

क्या अवैध धंधेबाजों के भी हो गए वारे-न्यारे...?

हालांकि चेकपोस्ट बंद करने के बाद सरकार नई कार्यप्रणाली के साथ काम करने के मुड में दिखाई दे रही है, लेकिन सरकार की यह नई कार्यप्रणाली कितनी कामयाब होगी यह समय के गर्त में है। अब तमाम परिवहन अधिकारी चेक पाइंट बनाकर वाहनों की चेकिंग करेंगे, लेकिन इस योजना को लेकर अभी तक कोई खुलासा सरकार के द्वारा नहीं किया गया है।

एक सवाल यह भी है कि जिन अवैध वसूली की षिकायतों को लेकर प्रदेश के चेकपोस्ट बंद किए गए क्या अब उस तरह की वसूली नहीं हो पाएगी..? यह प्रश्न हर किसी के मन में हिलौरे मार रहा है। क्योंकि चेकिंग चाहे जैसी हो करेगा तो परिवहन विभाग और उसके वही पुराने बागड़ बिल्ले। तो इस बात में कोई शंका नहीं है कि चेकपोस्ट बंद होने के बाद विभाग में बैठे बागड़ बिल्ले अवैध वसूली बंद कर देंगे। इसका मतलब सीधे तौर पर यह निकाला जा सकता है कि सरकार ने नए झोले में पुराना सामान ही जनता को वापस दे दिया है। मतलब चेकपोस्ट से होने वाली अवैध वसूली चेकपोस्ट पर ना होकर कहीं और होगी, मगर होगी जरूर...?

हालांकि मध्यप्रदेश शासन के इस आदेश के बाद विभाग में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अभी सरकार ने महज चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए है, आगे क्या करना है यह अभी तक विभाग को भी पता नहीं है। अब विभागीय अधिकारी इस इंतजार में है कि आगे शासन जैसा निर्णय लेगा और वरिष्ठ अधिकारी जैसे आदेश देंगे वैसे तूती हम बजाएंगे।

जो भी हो लेकिन सरकार के इस फैसले से आम माल वाहक वाहन चालक खुशी से झूम उठे है। सरकार के इस फैसले ने आम वाहन चालकों की कई गंभीर समस्याओं को समाप्त कर दिया है। जिससे अब वाहन चालकों को लंबी कतार, लंबे इंतजार और चेकपोस्ट पर होने वाली अवैध वसूली से तो फिलहाल राहत मिल ही गई है। इधर ट्रांसपोर्टरों का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश को व्यावसायिक रूप से लाभ मिलेगा। पहले वाहन मालिक और चालक दोनों ही प्रदेश की सीमा पार करने में संकोच करते दिखाई देते थे। उनके साथ कई तरह की समस्याएं होती थी। गुजरात से मध्यप्रदेश में आने और मध्यप्रदेश से गुजरात जाने के लिए वाहन मालिकों और चालकों को कई तरह का भय बना रहता था। जिसमें बार्डर पर लंबी कतार में खड़े होकर इंतजार करना, वाहन के कागजात में कमी के कारण अवैध वसूली का डर और कागजात पूरे होने की सूरत में भी हजारों रूपये इंट्री के रूप में देना वाहन चालकों को भारी लगता था। यही कारण था कि वाहन चालक बार्डर क्रास करने में संकोच करते थे और अन्य प्रदेशों के मिलने वाले भाड़े को नजर अंदाज करते थे। लेकिन अब पिटोल चेक पोस्ट के साथ ही प्रदेश की तमाम चेकपोस्ट मप्र शासन द्वारा बंद कर दी गई है। जिससे अब वाहन चालकों को अन्य प्रदेश में जाने हेतु संकोच नहीं करना पड़ेगा।

चेकपोस्ट बंद होने के बाद प्रदेश में अब सभी जांच चौकियों की जगह रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चैकिंग पाइंट बनाए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारियों के रूप में होमगार्ड की नियुक्तियां की जाएगी। ओव्हरलोडिंग चैक करने हेतु मोबाइल वेइंग मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। विभागीय स्टॉफ को बॉडी वॉर्न कैमरे दिए जाएंगे, जिसमें हर गतिविधि रिकार्ड होगी।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, अलका भटेवरा द्वारा काम्पेक प्रिन्टर्स प्रायवेट लिमिटेड, 3/54, प्रेस कॉम्प्लेक्स, ए. बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 499, बाजना मार्ग, गणेश मंदिर के सामने, खवासा, तहसील थांदला, जिला-झाबुआ (म.प्र.) से प्रकाशित। प्रधान संपादक- संजय भटेवरा। मोबाइल नं. -95898-82798 (सभी विवादों का न्यायालय क्षेत्र झाबुआ रहेगा) आरएनआई नंबर- एमपीएचआईएन/2018/76422